



श्री नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री

इंफ्रास्ट्रक्चर क्रांति

गांव से ग्लोबल कनेक्टिविटी तक

बदलता छत्तीसगढ़

मजबूत सड़कें, विस्तृत रेल नेटवर्क, डिजिटल कनेक्टिविटी और आधुनिक शहरों के दम पर विकास की नई पहचान गढ़ रहा छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ आज विकास के ऐसे दौर से गुजर रहा जहां इंफ्रास्ट्रक्चर केवल निर्माण कार्य नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का सबसे बड़ा माध्यम बन चुका है। गांवों को शहरों से, आदिवासी अंचलों को मुख्यधारा से और प्रदेश को राष्ट्रीय एवं वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ने के लिए सड़क, रेल, डिजिटल नेटवर्क, लॉजिस्टिक्स, शहरी विकास और ऊर्जा क्षेत्र में अभूतपूर्व निवेश किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने कनेक्टिविटी को विकास की सबसे बड़ी आधारशिला बनाया है। नई सड़कें गांवों तक पहुंच रही हैं, रेल नेटवर्क का विस्तार हो रहा है, डिजिटल सेवाएं दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंच रही हैं और आधुनिक शहरी परियोजनाएं नागरिक सुविधाओं को नई पहचान दे रही हैं। परिणामस्वरूप छत्तीसगढ़ अब केवल खनिज संपदा का राज्य नहीं, बल्कि उभरते हुए औद्योगिक, लॉजिस्टिक्स और डिजिटल हब के रूप में अपनी नई पहचान स्थापित कर रहा है।

विकसित छत्तीसगढ़ का सपना मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर कनेक्टिविटी के बिना संभव नहीं है। हमारी सरकार का लक्ष्य केवल सड़क, पुल, रेल लाइन या डिजिटल नेटवर्क बनाना नहीं, बल्कि विकास को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। आज बस्तर के वनांचल से लेकर सरगुजा के गांवों तक और राजधानी रायपुर से लेकर राष्ट्रीय बाजारों तक कनेक्टिविटी का एक नया नेटवर्क तैयार हो रहा है। डिजिटल भारतनेट परियोजना, नए एक्सप्रेस-वे, रेलवे कॉरिडोर, ग्रामीण सड़कें, नगरोत्थान योजना और बस्तर में चल रहे विकास कार्य मिलकर छत्तीसगढ़ को विकसित भारत की अग्रिम पंक्ति में खड़ा करेंगे। हमारा संकल्प है कि विकास का लाभ प्रदेश के हर गांव, हर परिवार और हर नागरिक तक पहुंचे।

- श्री विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़





सड़कों से खुल रहे विकास के नए द्वार

गांव-शहर की दूरी घट रही, अवसरों की दूरी मिट रही



- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत 2.225 करोड़ रुपये की लागत से 774 नई ग्रामीण सड़कों को मंजूरी।
- कुल लंबाई 2,426 किलोमीटर।
- मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा के माध्यम से लगभग 1,000 दूरस्थ गांव ने सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क से जुड़े।
- शिक्षा, स्वास्थ्य, बाजार और रोजगार तक पहुंच होगी आसान।

संदेश साफ है, जहां सड़क पहुंचेगी, वहां विकास पहुंचेगा।



एक्सप्रेस-वे से तेज हुई विकास की रफ्तार

उद्योग, व्यापार और निवेश को मिल रही नई दिशा



- रायपुर-विशाखापट्टनम एक्सप्रेस-वे और दुर्ग-रायपुर-आरंग एक्सप्रेस-वे प्रदेश को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक गलियारों से जोड़ रहे हैं।
- बंदरगाहों तक पहुंच आसान, माल परिवहन सस्ता और उद्योगों को नई प्रतिस्पर्धक क्षमता।
- NH-53 पर रायपुर से विश्वप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल सिरपुर तक यात्रा पहले से अधिक सुगम हुई।



रेलवे क्रांति: नई पटरी पर दौड़ता विकास

22 गुना बढ़ा रेलवे बजट, बदल रही प्रदेश की तस्वीर



- 2009-14 में रेलवे बजट औसतन 311 करोड़ प्रति वर्ष।
- अब बढ़कर 26,925 करोड़ प्रति वर्ष।
- नई रेल लाइनों, डबलिंग, मल्टी-ट्रेकिंग परियोजनाओं से प्रदेश का रेल नेटवर्क लगातार मजबूत।

मेगा रेल कॉरिडोर: भविष्य की नई धुरी

- खरसिया नया रायपुर-परमलकसा के बीच 28,741 करोड़ की लागत से 5वीं एवं 6वीं रेल लाइन परियोजना जारी।
- दल्लीराजहरा रावघाट-जगदलपुर नई रेल लाइन बस्तर को मजबूत करेगी।



डिजिटल कनेक्टिविटी: गांव-गांव तक इंटरनेट की पहुंच

3,942 करोड़ रुपये की भारतनेट परियोजना बनेगी डिजिटल जीवनरेखा



- 11,682 ग्राम पंचायतों को रिंग टोपोलॉजी आधारित हाई-स्पीड डिजिटल नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है।
- ई-गवर्नेंस, ऑनलाइन शिक्षा, टेलीमैडिसिन, डिजिटल बैंकिंग और ग्रामीण उद्यमिता को नई ताकत।



अबुझमाड़ तक पहुंची डिजिटल क्रांति

ताहकाडोंड में मोबाइल टावर ने बदली जिंदगी



4G संचरेशन प्रोजेक्ट से जुड़े दूरस्थ गांव डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन शिक्षा, बैंकिंग सेवाएं और सरकारी योजनाओं की जानकारी अब सीधे ग्रामीणों तक।



डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का नया केंद्र बन रहा नवा रायपुर

देश का पहला AI आधारित डेटा सेंटर पार्क



AI, क्लाउड सेवाएं, डेटा प्रोसेसिंग और डिजिटल नवाचार के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को नई पहचान। हजारों प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे।



लॉजिस्टिक्स और उद्योग में नई उपलब्धि

LEADS रिपोर्ट में 'हाई परफॉर्मर' बना छत्तीसगढ़

- LEADS 2025 रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ को 'हाई परफॉर्मर' राज्य का दर्जा
- बेहतर सड़क नेटवर्क, मजबूत परिवहन व्यवस्था और लॉजिस्टिक्स सुधार
- औद्योगिक विकास नीति 2024-30 और लॉजिस्टिक्स नीति निदेशकों के लिए नए अवसर।



शहरी विकास की नई तस्वीर

मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना से बदलेंगे शहर

- 13 नगर निगमों में 429.45 करोड़ रुपये की लागत से 26 बड़े प्रोजेक्ट्स मंजूर
- रायपुर में सड़क जंक्शन उद्घाटन, जलापूर्ति नेटवर्क विस्तार, महादेव घाट पुनर्विकास, तेलीबांधा में तकनीकी टॉवर निर्माण।
- आधुनिक, व्यवस्थित और नागरिक केंद्रित शहरों की दिशा में बढ़ा कदम।



ऊर्जा और नागरिक सुविधाओं का विस्तार

- नए सब-स्टेशनों और पॉवर नेटवर्क विस्तार से बेहतर और विश्वसनीय बिजली उपलब्ध।
- शहरों में सड़क चौड़ीकरण, जलापूर्ति, बस टर्मिनल, सार्वजनिक उद्यान और नागरिक सुविधाओं का विस्तार।
- जीवन स्तर में हो रहा उल्लेखनीय सुधार।

बस्तर में विकास का नया अध्याय



कोण्डागांव को मिली 152.19 करोड़ रुपये की ऐतिहासिक सौगात, 43 विकास कार्य

 77 करोड़ की लागत से 8.89 किमी लंबा कोण्डागांव बाईपास	 उच्च स्तरीय पुल निर्माण परियोजनाएं	 ग्राम पंचायत डिजिटल नेटवर्क से जुड़ेगी	 सिंचाई एवं जल संरक्षण कार्य	 नए विद्युत उपकेंद्र	 महतारी सदन और दीदी की रसोई जैसी परियोजनाएं	 स्कूल भवन और ग्रामीण अधोसंरचना विकास
---	---	--	--	--	---	---

कनेक्टिविटी, सिंचाई, पेयजल, शिक्षा और ऊर्जा सुविधाओं को मिलेगी नई मजबूती

 ₹3,942 करोड़ भारतनेट परियोजना	 11,682 ग्रामीण जल प्रदाय योजनाएं	 ₹8,741 करोड़ मेगा रेल कॉरिडोर परियोजना	 ₹2,225 करोड़ PMGSY 774 नई सड़कें	 ₹429.45 करोड़ नगरोत्थान योजना	 ₹152.19 करोड़ कोण्डागांव विकास कार्य
--	---	---	---	--	---

विकसित छत्तीसगढ़ की ओर मजबूत कदम

मजबूत कनेक्टिविटी • आधुनिक अधोसंरचना • डिजिटल सशक्तीकरण • समृद्ध छत्तीसगढ़



संपादक-48873/2

संक्षिप्त समाचार

प्रसिद्ध भागवताचार्य इन्द्रेशजी महाराज की श्रीमद्भागवत कथा 21 से 27 सितंबर को

रायपुर। प्रसिद्ध भागवताचार्य एवं युवा आध्यात्मिक वक्ता श्री इन्द्रेशजी महाराज की श्रीमद्भागवत कथा 21 से 27 सितंबर को राजधानी रायपुर के कृषि उपज मंडी ग्राउंड देवेन्द्रनगर में होने जा रहा है। इस सप्तदिवसीय श्रीमद्भागवत कथा की व्यापक तैयारी की जा रही क्योंकि काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन महाराजश्री की कथा का श्रवण करने पहुंचने वाले हैं। आयोजन को लेकर श्रद्धालुजनों में भारी उत्साह है। महाराजश्री 20 सितंबर को राजधानी रायपुर पहुंचेगे जहां सर्वसमाज के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। 21 सितंबर को श्रीराम मंदिर कृषि उपज मंडी देवेन्द्रनगर से भव्य कलश यात्रा निकलेगी जिसमें 21 हजार महिलाएं पीली साड़ी में होंगी वहीं पुरुष कुर्ता-पैजाम पहने हुए होंगे। प्रमुख सेवादारी गुंजन प्रजापति ने आयोजन के संदर्भ में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उक्त जानकारी दी। इस दौरान सभी समाज के प्रमुख लोग उपस्थित थे। गुंजन प्रजापति ने बताया कि पुन्य श्री इन्द्रेश जी महाराज के बारे में सनातनी लोगों को बताने की जरूरत नहीं हैं। जिनकी वाणी में श्री हरि की भक्ति, विचारों में सनातन संस्कृति की सुगंध और संदेशों में जीवन को सही दिशा देने की प्रेरणा है, उनको कथा हृदय को भक्ति से जोड़ने का एक सुंदर माध्यम है। कथा स्थल का आयोजन कृषि उपज मंडी ग्राउंड देवेन्द्रनगर में इसलिए किया जा रहा है कि न केवल शहर बल्कि बाहर शहरों से आने वाले श्रद्धालुओं को भी सुविधा होगी और हजारों की संख्या में श्रद्धालु सुविधाजनक ढंग से बैठकर कथा श्रवण कर सकेंगे।

काव्योपाध्याय हीरालाल कॉलेज में अतिथि व्याख्याता (समाजशास्त्र) पद पर होगी भर्ती



महाविद्यालय, अभनपुर जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा समाजशास्त्र विषय में अध्यापन कार्य हेतु अतिथि व्याख्याता के 01 रिक्त पद पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित योग्यता अनुसार अपना आवेदन पत्र पंजीकृत डाक के माध्यम से 23 सितंबर 2026 शाम 5:30 बजे तक भेज सकते हैं या स्वयं महाविद्यालय में उपस्थित होकर जमा कर सकते हैं या अधिकृत वेबसाइट- 222.द्वयद्वय.द्वुड में भेजा जा सकता है। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। विस्तृत नियम एवं शर्तों की जानकारी के लिए अभ्यर्थी महाविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

महतारी वंदन से सशक्त हो रही

छत्तीसगढ़ की नारी शक्ति

रायपुर। महतारी वंदन योजना महिलाओं के लिए आर्थिक संबल और आत्मविश्वास का महत्वपूर्ण आधार बन रही है। योजना के माध्यम से महिलाओं को मिलने वाली नियमित आर्थिक सहायता उन्हें अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ परिवार की जरूरतों में सहयोग करने और आर्थिक निर्णयों में अधिक आत्मविश्वास के साथ भागीदारी का अवसर दे रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने महिला नेतृत्व वाले विकास को विकसित भारत 2047 की यात्रा का महत्वपूर्ण आधार बताया है। उनका विजन है कि महिलाएं केवल विकास की लाभार्थी न रहें, बल्कि विकास की नेतृत्वकर्ता और भागीदार बनें। वित्तीय समावेशन, उद्यमिता, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, स्वच्छता और शासन सहित विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भूमिका इसी सोच को आगे बढ़ाती है। इसी व्यापक सोच का जमीनी प्रभाव गौरीला-पेंड्रा-मरवाही जिले के ग्राम साबबहरा की श्रीमती कविता चक्रधारी के जीवन में भी दिखाई देता है। श्रीमती कविता महतारी वंदन योजना की हितग्राही हैं। उन्होंने बताया कि योजना की 31वीं किस्त की राशि उनके बैंक खाते में प्राप्त हो गई है। उनके लिए यह राशि रोममर्रा की छोटी-छोटी जरूरतों को पूरा करने में उपयोगी साबित हो रही है।

अनाधिकृत वेंडरों के विरुद्ध रायपुर रेल मंडल की सघन जांच एवं कार्रवाई

रायपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, रायपुर रेल मंडल द्वारा यात्रियों की सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण एवं अधिकृत खानपान सामग्री उपलब्ध कराने तथा रेलवे परिसर में अनाधिकृत गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से अनाधिकृत वेंडरों के विरुद्ध सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। अधिकृत वेंडरों के माध्यम से गाडियों तथा स्टेशनों में गुणवत्तायुक्त खानपान की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। स्टेशनों एवं गाडियों में यात्रियों को उपलब्ध कराई गई खानपान की गुणवत्ता को बरकरार रखने तथा उसमें लगातार सुधार हेतु प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया जा रहा है। रायपुर रेल मंडल के प्रमुख रेलवे स्टेशनों एवं ट्रेनों में वाणिज्य विभाग तथा रेलवे सुरक्षा बल के सहयोग से जांच की जा रही है। इस दौरान ऐसे व्यक्तियों की पहचान की जा रही है जो बिना वैध अनुमति/लाइसेंस के स्टेशन परिसर अथवा ट्रेनों में खाद्य सामग्री, पेय पदार्थ एवं अन्य यात्रियों को उपयोगी वस्तुओं की बिक्री करने का प्रयास करते हैं। रेलवे प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि केवल अधिकृत एवं वैध लाइसेंसधारी वेंडरों को ही रेलवे परिसर एवं ट्रेनों में निर्धारित नियमों के अनुसार बिक्री की अनुमति है। अनाधिकृत रूप से खाद्य सामग्री अथवा अन्य वस्तुओं की बिक्री करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

राजधानी/छत्तीसगढ़

भविष्य के उद्योगों का नया केंद्र बनने की ओर अग्रसर छत्तीसगढ़ : मुख्यमंत्री

विष्णुदेव साय ने रायपुर में किया ‘इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर-2026’ का शुभारंभ

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने शुक्रवार को राजधानी रायपुर के साईंस कॉलेज मैदान में लघु उद्योग भारती द्वारा आयोजित तीन दिवसीय ‘इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर-2026’ का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने देश के विभिन्न राज्यों से आए उद्यमियों, निवेशकों और औद्योगिक प्रतिनिधियों का छत्तीसगढ़ की धरती पर स्वागत करते हुए उन्हें प्रदेश की विकास यात्रा में सहभागी बनने और यहां उपलब्ध निवेश की व्यापक संभावनाओं का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ आज अपनी पारंपरिक औद्योगिक ताकत के साथ नई अर्थव्यवस्था और उभरते उद्योगों की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। खनिज, ऊर्जा, वन संपदा, पर्याप्त मानव संसाधन और देश के मध्य में अनुकूल भौगोलिक स्थिति हमारी स्वाभाविक ताकत है। राज्य सरकार इन खूबियों को आधुनिक तकनीक, बेहतर अधोसंरचना और निवेशक हितैषी नीतियों से जोड़कर छत्तीसगढ़ को देश के प्रमुख औद्योगिक एवं निवेश गंतव्यों में स्थापित करने की दिशा में कार्य कर रही है।

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की भूमिका केवल उद्योगों के लिए नियामक की नहीं है। हम सरकार को उद्योग और निवेश को राह आसान करने वाले सहयोगी और ‘एक्सीलरेटर’ के रूप में विकसित कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि निवेश का प्रस्ताव आने से लेकर उद्योग के धरातल पर स्थापित होने तक हर चरण में निवेशकों को सरल,

पारदर्शी और समयबद्ध व्यवस्था मिले। मुख्यमंत्री ने लघु उद्योग भारती द्वारा राष्ट्रीय स्तर के इस महत्वपूर्ण औद्योगिक आयोजन के लिए रायपुर का चयन किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था की मजबूत आधारशिला हैं। बड़े उद्योगों के साथ एमएसएमई का विस्तार होने से स्थानीय स्तर पर उद्यमिता बढ़ती है, रोजगार के अवसर पैदा होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का लाभ समाज के व्यापक वर्ग तक पहुंचता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लघु उद्योग भारती देशभर के 750 से अधिक जिलों में उद्यमियों को संगठित कर उद्योग और उद्यमिता को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। छत्तीसगढ़ के 25 जिलों में भी 1200 से अधिक लघु एवं मध्यम उद्योग संगठन से जुड़े हैं। 18 से 20 सितम्बर तक आयोजित इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर में देशभर के 300 से अधिक एमएसएमई उद्यमियों का भागीदारी इस आयोजन के महत्व को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि यह औद्योगिक मेला केवल उत्पादों और तकनीकों की प्रदर्शनी नहीं है। यह उद्यमियों के बीच संवाद, अनुभव, नवाचार और तकनीकी ज्ञान के आदान-प्रदान का महत्वपूर्ण मंच है। इसके माध्यम से नए व्यावसायिक संबंध बनेंगे, नई संभावनाओं पर चर्चा होगी और युवाओं को उद्योग तथा उद्यमिता की दुनिया को करीब से समझने का अवसर मिलेगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़



सरकार ने उद्योग जगत, निवेशकों और विभिन्न हितधारकों से व्यापक विचार-विमर्श के बाद औद्योगिक विकास नीति 2024-30 लागू की है। इस नीति का उद्देश्य केवल निवेश आकर्षित करना नहीं, बल्कि ऐसा औद्योगिक इकोसिस्टम तैयार करना है, जिसमें निवेश, उत्पादन, रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था एक साथ आगे बढ़ें। उन्होंने कहा कि नई औद्योगिक नीति में प्रक्रियाओं के सरलीकरण, निवेशकों को प्रोत्साहन, नए एवं उभरते सेक्टरों को बढ़ावा और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार सृजन को विशेष प्राथमिकता दी गई है। नीति लागू होने के बाद प्रदेश को बड़े पैमाने पर निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और प्रसन्नता की बात है कि अनेक परियोजनाओं पर धरातल पर काम भी प्रारंभ हो चुका है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ अब केवल कोयला, स्टील और सीमेंट जैसे पारंपरिक उद्योगों तक सीमित नहीं है। राज्य

सरकार प्रदेश के औद्योगिक आधार को विविधता देने के लिए आईटी, सेमीकंडक्टर, फार्मा, टेक्सटाइल, ग्रीन एनर्जी सहित विभिन्न नए और भविष्य की अर्थव्यवस्था से जुड़े क्षेत्रों को प्रोत्साहित कर रही है। प्रदेश में लगभग 1100 करोड़ रुपए की सेमीकंडक्टर परियोजना पर कार्य प्रारंभ होना इस बदलते औद्योगिक परिदृश्य का उदाहरण है। उन्होंने कहा कि नवा रायपुर को आधुनिक टेक्नोलॉजी हब के रूप में विकसित करने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। यहां आधुनिक अधोसंरचना के साथ नए उद्योगों और तकनीक आधारित कंपनियों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया जा रहा है। राज्य में टेक्नोलॉजी हब और इंडस्ट्री एक्सिलेंस हब विकसित करने की दिशा में भी सरकार आगे बढ़ रही है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि किसी भी राज्य में उद्योग तभी तेजी से आगे बढ़ सकते हैं, जब निवेशकों को नीतिगत स्थिरता के साथ सरल और पारदर्शी प्रक्रियाएं मिलें। इसी सोच के साथ राज्य सरकार ने सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से उद्योग स्थापना से जुड़ी प्रक्रियाओं को आसान बनाने की दिशा में काम किया है, ताकि निवेशकों को विभिन्न कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़ें। उन्होंने कहा कि उद्योगों को समय पर आवश्यक भूमि, अधोसंरचना और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार चाहती है कि उद्यमी अपना समय और ऊर्जा प्रक्रियागत

जटिलताओं में लगाने के बजाय उत्पादन, नवाचार, विस्तार और रोजगार सृजन में लगाएं। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से देश के सबसे समृद्ध राज्यों में शामिल है। कोयला, लौह अयस्क और बॉक्साइट सहित अनेक महत्वपूर्ण खनिज यहां प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। इन संसाधनों का प्रदेश के भीतर अधिक से अधिक मूल्य संवर्धन हमारी औद्योगिक रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ का 44 प्रतिशत से अधिक भू-भाग वनाच्छादित है। प्रदेश में इमली, महुआ, चिरौंजी, हर्रा-बहेड़ा सहित अनेक प्रकार की लघु वनोपज और औषधीय संसाधन उपलब्ध हैं। इनका वैज्ञानिक प्रसंस्करण और वैल्यू एडिशन कर वनांचल में उद्योग एवं रोजगार की नई संभावनाएं विकसित की जा सकती हैं। इससे स्थानीय समुदायों और जनजातीय परिवारों की आय बढ़ाने के भी नए रास्ते खुलेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र छत्तीसगढ़ की औद्योगिक क्षमता का एक और मजबूत आधार है। प्रदेश में लगभग 30 हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता है। ऊर्जा क्षेत्र में नए निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं और आने वाले वर्षों में उत्पादन क्षमता को और बढ़ाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। पर्याप्त बिजली, जल संसाधन, मानव संसाधन, प्राकृतिक संपदा और देश के मध्य में स्थित होने का भौगोलिक लाभ छत्तीसगढ़ को उद्योगों के लिए स्वाभाविक रूप से अनुकूल बनाता है।

नगर पंचायत में बीजेपी पार्षदों का सामूहिक इस्तीफा सामान्य बात : मंत्री जायसवाल

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजनीतिक गलियारों में रायगढ़ के पुसौर नगर पंचायत के 8 पार्षदों के सामूहिक इस्तीफे से खलबली मच गई है। त्याग पत्र में पार्षदों ने नगर पंचायत अध्यक्ष की कार्यप्रणाली और विकास कार्यों को लेकर नाराजगी जाहिर की है। इस घटनाक्रम के बीच अब स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान सामने आया है।

मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने घटनाक्रम को सामान्य बात बताया है। उन्होंने कहा कि राजनीति में अलग-अलग परिस्थितियों और कारणों के चलते लोग इस्तीफा देते रहते हैं।

बता दें कि रायगढ़ भाजपा जिलाध्यक्ष अरुणधर दीवान को त्याग पत्र साँपने वाले पुसौर नगर पंचायत के पार्षदों में वार्ड 6 पार्षद बलराम, वार्ड 14 पार्षद शौकीलाल चौहान, वार्ड-11 पार्षद रूपेश कुमार साव,



वार्ड 1 पार्षद प्रदीप यादव, वार्ड 2 पार्षद फागुलाल प्रधान, वार्ड-3 पार्षद मंजू पटेल, वार्ड 7 पार्षद वरुण महाणा और नगर पंचायत उपाध्यक्ष उमेश साव शामिल हैं।

पार्षदों ने त्याग पत्र में अपनी पीड़ा बताते हुए लिखा है कि शासकीय कर्मचारियों और नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा किये जा रहे उत्पीड़न एवं विकास कार्य की शून्यता को लेकर हम सभी अत्यंत पीड़ा में हैं। हमारे वार्ड में जन सुविधा हेतु विकास कार्य पानी, बिजली, रोड नाली, व अन्य विकास कार्य नहीं किये जा रहे हैं। पार्षद निधि का भी कार्य नहीं हो रहा हैं। ऐसे में पार्टी से

त्याग पत्र देना उचित है।

‘आशीर्वाद का दीया’ कार्यक्रम के खर्च को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सवाल पूछे किए हैं। उनके सवालों पर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि एक-एक दीए का जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनता ही इन सवालों का जवाब देगी। जितना जवाब चाहिए, उसका जवाब 2028 के विधानसभा चुनाव में जनता दे देगी।

कांग्रेस के सरगुजा की 14 विधानसभा सीटों पर वापसी करने के दावों पर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने तन कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सपने देखे, सपने देखने में कुछ नहीं जाता। जब कांग्रेस के पास 14 सीटें थीं, तब वह उन्हें संभाल नहीं पाई और आज उनके पास एक भी सीट नहीं है। उन्होंने कहा कि सरगुजा में कांग्रेस जीरो सीटों की हैट्टिक करेगी।

प्रदेश की दीर्घकालिक अधोसंरचना विकास की बनेगी समग्र कार्ययोजना

रायपुर। प्रदेश में अधोसंरचना विकास को गति देने और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप मजबूत एवं एकीकृत अधोसंरचना तैयार करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन के संबंध में शुक्रवार को मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। लोक निर्माण विभाग को मिशन का नोडल विभाग बनाया गया है।

बैठक में मिशन के तहत प्रदेश के सड़क, ऊर्जा, ट्रांसमिशन, जल, सिंचाई, संचार, फाइबर नेटवर्क तथा अन्य आवश्यक अधोसंरचना के समग्र विकास के लिए दीर्घकालिक रणनीति और कार्ययोजना तैयार करने पर चर्चा हुई। मुख्य सचिव श्री विकासशील ने प्रदेश के रोड नेटवर्क के लिए आगामी 20 वर्षों का मास्टर प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मास्टर प्लान में वर्तमान अधोसंरचना की स्थिति, भविष्य की जरूरतों, कनेक्टिविटी की आवश्यकताओं और संभावित विकास क्षेत्रों का समग्र आकलन किया जाए। इसके आधार पर प्राथमिकता तय कर उनके क्रियान्वयन को कार्ययोजना तैयार की जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में सड़क कनेक्टिविटी के साथ ऊर्जा, जल, सिंचाई, संचार एवं डिजिटल कनेक्टिविटी सहित सभी प्रमुख अधोसंरचना घटकों को एकीकृत दृष्टिकोण के साथ देखा जाए। प्रत्येक क्षेत्र की आवश्यकता का आकलन कर यह निर्धारित किया जाए कि आने वाले वर्षों में किस प्रकार की अधोसंरचना और किन क्षेत्रों में विकसित की जानी है।

मुख्य सचिव ने प्रदेश में इंटरमॉडल ट्रांसपोर्ट एवं लॉजिस्टिक्स हब विकसित करने की संभावनाओं का अध्ययन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सड़क एवं रेल सहित विभिन्न परिवहन माध्यमों के बीच



बेहतर कनेक्टिविटी विकसित करने तथा माल परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक परियोजनाओं को चिन्हित करने को कहा। उन्होंने अधोसंरचना परियोजनाओं के लिए नए फंडिंग मैकेनिज्म की संभावनाओं का भी अध्ययन करने के निर्देश दिए। निजी एवं सार्वजनिक निवेश सहित विभिन्न वित्तीय विकल्पों का परीक्षण कर परियोजनाओं के लिए उपयुक्त वित्तीय व्यवस्था विकसित करने पर जोर दिया।

मुख्य सचिव ने कहा कि 20 वर्षीय मास्टर प्लान के साथ वार्षिक एक्शन प्लान भी तैयार किया जाए। इसमें प्रत्येक वर्ष प्रस्तावित कार्यों, उनकी प्राथमिकता, आवश्यक संसाधनों और समय-सीमा का स्पष्ट निर्धारण हो। उन्होंने परियोजनाओं की प्रॉपर प्लानिंग एवं मैपिंग के साथ उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने देश के अन्य राज्यों में विकसित की जा रही आधुनिक अधोसंरचना परियोजनाओं का अध्ययन करने के लिए अधिकारियों के एक्सपोजर विजिट आयोजित करने को भी कहा, इससे वहां अपनाई जा रही बेहतर तकनीकों एवं कार्यप्रणालियों को छत्तीसगढ़ की आवश्यकताओं के अनुरूप अपनाया जा सके। मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए मिशन के कार्यों को समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए।

झीरम हत्याकांड : 10 आरोपियों को फांसी की सजा

■ एनआईए की जांच में कई अहम खुलासे

रायपुर/जगदलपुर। झीरम हत्याकांड का जजमेंट आ चुका है। इस मामले की जजमेंट कापी भी सामने आ गई है। जजमेंट में 25 फरवरी 2013 से लेकर 25 मई के हमले तक की पूरी साजिश और नक्सलियों की तैयारियों को लेकर कई अहम बातें सामने आई हैं। झीरम घाटी हत्याकांड मामले में एनआईए कोर्ट ने 10 आरोपियों को मौत की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अपने फैसले में 26/11 मुंबई हमले की नजिर का भी उल्लेख किया है।

जजमेंट के मुताबिक, 25 फरवरी 2013 को झीरम घाटी की घटना को अंजाम देने की साजिश रची गई थी। साउथ रीजनल सुनिफाइड कमांड की बैठक में यह निर्णय लिया गया था। झीरम घाटी हमले की संचालन की जिम्मेदारी बारसे देवा और सुरेंद्र को दी गई थी। बारसे देवा और सुरेंद्र ने टीसीओसी के दौरान दरभा डिवीजन में बड़ी घटना करने का प्रस्ताव मीटिंग में रखा था। इस बैठक में देवजी और गणेश उड़के ने नक्सली कमांडर जयलाल को सीआरसी कंपनी 2 की टुकड़ी के साथ दरभा डिवीजन में भेजा था। देवजी, गणेश उड़के, बारसे देवा और सुरेंद्र को एंबुश की जगह चुनने और एसजेडसी श्याम और सुरेंद्र को सामान इकट्ठा करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इस घटना को अंजाम देने के लिए नक्सली नेता गणपति और रमन्ना ने मंजूरी दी थी।

मुख्य रूप से इस घटना में बड़े नक्सलियों में सुरेंद्र, बारसे



देवा ,जयलाल, विनोद, सोनाधार और करीब 150 से अधिक नक्सली शामिल थे। घटना वाले दिन अभियुक्त प्रमिला, बंजामी सन्ना, आयता मड़ुकाम, मुक्का माड़वी, मड़ुकामी देवा, चेत्तू लेकाम ,कवासी कोसा, महादेव नाग, जोगा मड़ुकामी और सुमित्रा व कोसाराम शामिल थे।

कवासी कोसा की मृत्यु हो चुकी है। इस घटना में प्रमिला मड़ियाम बंजामी सन्ना, महादेव नाग ने जवानों के हथियार लूटे, इसके अलावा इस घटना की अंजाम देने से पहले नक्सली संगठन की अलग-अलग टुकड़ियों में हुई बैठक में मुख्य रूप से शामिल रहे। खुद अपने बयान में अभियुक्त चैत्तू लेकाम ने बताया कि घटना के दिन वो खुद और प्रमिला ने काफिले पर गोली चलाई, चैत्तू ने अपने इंसास राइफल से 10 राउंड फायर किया और प्रमिला ने अपने राइफल से भी गोलीया चलाई। इसके अलावा अन्य अभियुक्त ने बैठक के दौरान और घटना के दो दिन पूर्व नक्सलियों के लिए राशन सामान लाने, घटना के बाद हथियार लूटने, का काम किया। अपने बयान में खुद अभियुक्तों ने बताया कि वह पहले से ही नक्सल संगठन में जुड़े हुए थे। दरभा थाना में मुक्का माड़वी,

रही है।इस अवधि में देश ने विकास और जनकल्याण के अनेक क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन देखा है। गरीबों के पक्के आवास से लेकर स्वच्छ पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य सुविधाओं, स्वच्छता, वित्तीय समावेशन और बुनियादी अधोसंरचना तक जनकल्याणकारी योजनाओं ने करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव लाने का काम किया है।

कार्यक्रम के दौरान ‘आशीर्वाद का दीया’ आयोजन को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किए जाने की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री साय ने इस उपलब्धि पर रायपुरवासियों, आयोजन से जुड़े सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों, स्वयंसेवकों और जिला प्रशासन की पूरी टीम को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि इतनी व्यापक जनभागीदारी ने इस आयोजन को यादगार बना दिया है।

नंदकुमार पटेल और उनके बेटे दिनेश पटेल और कवासी लखमा को बंधक बनाए जाने का भी जजमेंट में उल्लेख है। एनआईए की जांच में 101 गवाहों के बयान और 207 साक्ष्य दस्तावेज कोर्ट के सामने पेश किए गए।

झीरम मामले में कुल 39 लोग आरोपी बनाए गए, जिसमें से 11 आरोपी पर ट्रायल चला और अभी भी 27 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, जिस पर एनआईए कोर्ट ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

फरार 27 आरोपियों में से 14 आरोपी मुख्य धारा में लौट आए हैं, जबकि 9 आरोपी अलग-अलग मुद्देबंद में मारे गए हैं। अन्य चार नक्सली भी सरेंडर किए हैं या मारे गए हैं।

<

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपराजेय क्यों हैं?

हसमुख अधिया

मोदी जी ने लगातार 25 वर्षों तक कई क्षेत्रों में सफलता हासिल की है। इनमें देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत और टिकाऊ गति देना, केंद्र में तीन बार चुनाव जीतना और कई राज्यों में चुनावों में सफलता हासिल करना शामिल है। इन उपलब्धियों के पीछे मोदी जी का व्यक्तित्व और उनके प्रबंधन, मानवीय तथा आध्यात्मिक गुण हैं। मुझे 2001 में पहली बार गुजरात का मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही राज्य और केंद्र, दोनों स्तरों पर मोदी जी के साथ काम करने का अवसर मिला। मैंने मुख्यमंत्री कार्यालय में एक वर्ष तक अतिरिक्त प्रधान सचिव और फिर दो वर्ष तक प्रधान सचिव के रूप में भी काम किया। इस दौरान मुझे उनके कई उत्कृष्ट गुणों को करीब से देखने का अवसर मिला। आइए, सबसे पहले उनके प्रबंधन के गुणों की बात करते हैं। पहला, वे हमेशा देश के भविष्य को ध्यान में रखकर दूरगामी सोच रखते हैं। लंबे समय के लिए योजना बनाने की उनकी क्षमता ही उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। दूसरा, वे हर किसी को देखते हैं, उनकी बात सुनते हैं और उनसे सीखते हैं। मुझे याद है कि केंद्रीय बजट तैयार करने के दौरान वे वित्त मंत्रालय के हर विभाग की प्रस्तुति को घंटों ध्यान से सुनते थे। इसके बाद बैठक में मौजूद लोगों के साथ विस्तार से चर्चा करते और अंत में अपनी राय रखते थे। तीसरा, वे आयुष्य मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय और खेल मंत्रालय सहित हर मंत्रालय के कामकाज की लगातार समीक्षा करते थे। इन बैठकों में वे संबंधित मंत्रालयों को नई और बेहतर दिशा देने के साथ ही उनका उत्साह भी बढ़ाते थे। चौथा, उन्होंने गुजरात में वरिष्ठ अधिकारियों के लिए ‘चिंतन शिविर’ के रूप में सालाना बैठक आयोजित करने की अच्छी परंपरा शुरू की। यह बड़े संगठनों में अपनाई जाने वाली एक बेहतरीन प्रबंधन पद्धति है। बाद में केंद्र में भी इसे वार्षिक मुख्य सचिव सम्मेलन के रूप में लागू किया गया। पांचवां, एक अच्छे टीम प्रबंधक के रूप में मैंने उन्हें हमेशा अधिकारियों और सहयोगियों के लिए सहजता से उपलब्ध पाया। उनकी यह उपलब्धता उन्हें आसपास हो रही गतिविधियों की सही जाचकारी देती थी। छठा, मोदी जी किसी भी नई पहल को शुरू करने और उसे व्यवस्थित करने में पूरा ध्यान देते थे। इसका उदाहरण पहली बार आयोजित किया गया ‘वाइब्रेंट गुजरात’ सम्मेलन है। इसके बाद वे चाहते थे कि उस अनुभव को सही ढंग से दर्ज किया जाए और उसे एक स्थायी व्यवस्था का हिस्सा बनाया जाए, ताकि भविष्य में भी उसका लाभ मिल सके। मोदी जी के मानवीय गुणों की बात करें तो गरीबों और वंचितों के प्रति उनके मन में सच्ची संवेदना है। मुझे वर्ष 2003 में गुजरात के पहले चिंतन शिविर में दिया गया उनका समापन भाषण याद है। इसमें उन्होंने वंचित लोगों की परेशानियों को इतनी भावुकता से बताया कि अधिकारिश अधिकारियों और मंत्रियों की आंखों में आंसू आ गए थे। अपनी टीम के प्रति भी उनका मानवीय जुड़ाव उतना ही गहरा है। जब उन्हें पता चलता है कि कोई अधिकारी या राजनीतिक कार्यकर्ता या उसके परिवार का कोई सदस्य बीमार है, तो वे फोन करके उसका हालचाल पूछते हैं। वे लोगों को उनके खास मौकों पर शुभकामनाएं भी देते हैं। एक ईंसान के रूप में उनकी सबसे खास बात यह है कि वे जिन लोगों से मिलते हैं, उनके नाम याद रखते हैं। कई साल बाद मिलने पर भी उन्हें नाम से पहचान लेते हैं। इससे लोग बहुत प्रभावित होते हैं। यह उनकी सहज और स्वाभाविक क्षमता है। मोदी जी के व्यक्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण पहलू उनके आध्यात्मिक गुण हैं। काम करने का उनका तरीका और जीवन में अच्छे या बुरे परिणामों को स्वीकार करने का उनका भाव भगवद्गीता में बताए गए कर्मयोग को दर्शाता है।

भारतीय दार्शनिक सम्प्रदाय

4-बौद्ध दर्शन का अनात्मवाद

गतांग आगे...

जिस प्रकार बौद्ध धर्म तथा बौद्ध दर्शन का यह मूलभूत सिद्धान्त है कि सर्वे दुःखम् अर्थात् सब कुछ दुःखमय है, उसी प्रकार उसी सिद्धान्त से सम्बन्ध रखने वाला दूसरा यह भी सिद्धान्त है कि सर्वमानात्मम् अर्थात् इस जगत् में जो कुछ भी है वह आत्मा से शून्य है।

बौद्धों के अनात्मतत्त्व को ठीक ठीक दार्शनिक रूप में नहीं समझा गया है। बौद्धों के सारे दार्शनिक सम्प्रदाय अनात्मवाद के सिद्धान्त के ही आश्रित है। यह अनात्मवाद का सिद्धान्त ही बौद्ध दर्शन और वैदिक दर्शन के बीच में विभाजक रेखा है। किसी विशेष सिद्धान्त की दृष्टि से कई बौद्ध दार्शनिक सम्प्रदाय और कई वैदिक दार्शनिक सम्प्रदाय एक जगह आ जाते हैं और किसी दूसरे सिद्धान्त की दृष्टि से दोनों धर्मों के कई दार्शनिक सम्प्रदाय परस्पर समान होने से एक और समान कैम्प में चले जाते हैं,

उदाहरणार्थ थेरावादी बौद्ध या किसी अंश तक वैभाषिक और न्याय वैशेषिक तथा मीमांसक दोनों ही बाह्यार्थवादी हैं।

दूसरी ओर बौद्ध दार्शनिक सम्प्रदाय योगाचार और शून्यवाद तथा वैदिक दार्शनिक सम्प्रदाय वेदान्त दोनों ही बाह्यार्थ के विरोधी हैं और वे इस अंश में परस्पर समान हैं। परन्तु वह सिद्धान्त, जिसमें प्रत्येक बौद्ध दार्शनिक सम्प्रदाय एक ओर है और प्रत्येक वैदिक दार्शनिक सम्प्रदाय दूसरी ओर, अनात्मवाद का है। अनात्मवाद का क्या अर्थ है?

साधारणतया यह समझा जाता है कि अनात्मवाद का तात्पर्य यह है कि बौद्ध वैदिक दर्शनों के समान ज्ञान धारा के अतिरिक्त इस ज्ञान धारा का आधाररूप कोई स्थिर आत्मा नहीं मानते। परन्तु प्रत्येक वैदिक दर्शन किसी न किसी रूप में स्थिर आत्मा को मानता है।

क्रमशः ...



ज्ञान/मीमांसा

प्रधानमंत्री मोदी कैसे विश्व के ताकतवर नेता बन गए?

कमलेश पांडे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक क्षेत्रीय नेता से वैश्विक पटल पर सबसे प्रभावशाली शीर्ष नेताओं में शामिल होना, उनकी सुदृढ़ रणनीतिक सोच, जनसंपर्क क्षमता और कूटनीतिक दूरदर्शिता का परिणाम है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय राजनीति के सबसे प्रमुख और चर्चित चेहरों में से एक हैं। देश की जनता उन्हें अलग-अलग दृष्टिकोणों से देखती है, और विपक्षी नेताओं के साथ उनके राजनीतिक समीकरणों के पीछे कई रणनीतिक कारण हैं।

तो आइए सबसे पहले उनके प्रमुख गूढ़ राजनीतिक गुण निम्नलिखित हैं-

एक, रणनीतिक कूटनीति और बहु-ध्रुवीय संतुलन: पीएम मोदी ने पारंपरिक गुटनिपेक्षता की नीति को बदलते हुए मल्टी-अलाइमेंट की रणनीति अपनाई। भारत ने एक ही समय में अमेरिका, रूस, यूरोप और मध्य-पूर्व (खाड़ी देशों) के साथ मजबूत व्यापारिक और सुरक्षा संबंध बनाए रखे हैं। रूस-यूक्रेन संघर्ष के बीच वैश्विक दबावों के बावजूद भारत के राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखना और वैश्विक दक्षिण की आवाज बनना उनकी मजबूत कूटनीतिक क्षमता को दर्शाता है।

दो, दूरदर्शी जन-संचार और ब्रांडिंग: मोदी जी जन-संवाद के अद्वितीय विशेषज्ञ हैं। मन की बात, विशाल जनसभाओं और सोशल मीडिया के माध्यम से वे जनता से सीधे जुड़ते हैं। उन्होंने भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को वैश्विक मंचों (जैसे- योग दिवस, जी-20 की भारत की अध्यक्षता, ब्रिक्स की अध्यक्षता) पर प्रस्तुत कर देश की सॉफ्ट पावर को अत्यधिक मजबूत किया है।

तीन, साहसिक और निर्णायक निर्णय क्षमता: राजनीतिक जोखिम उठाने और बड़े फैसले लेने में वे झिझकते नहीं हैं। सर्जिकल स्ट्राइक, धारा 370 का निष्प्रभावीकरण, जीएसटी, और डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं से उन्होंने यह संदेश दिया कि वे दीर्घकालिक राष्ट्रीय हित के लिए कड़े कदम उठाने में सक्षम हैं।

चार, तकनीकी और कल्याणकारी सुशासन: डिजिटल इंडिया, आधार और यूपीआई के समावेश से सीधे बैंक खातों में जन-कल्याणकारी योजनाओं का पैसा पहुंचाकर उन्होंने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया और प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाई। इस मॉडल को वैश्विक स्तर पर एक सफल उदाहरण के रूप में देखा जाता है।



पांच, कैडर संगठन और विशाल राजनीतिक तंत्र: जमीनी स्तर पर काम करने और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं भारतीय जनता पार्टी के कैडर संगठन का गहरा अनुभव उनकी सबसे बड़ी ताकत है। वे केवल नीतियों पर ध्यान केंद्रित नहीं करते, बल्कि उन नीतियों को धरातल पर उतारने के लिए पार्टी कैडर और नौकरशाही का कुशलता से उपयोग करते हैं।

प्रधानमंत्री मोदी की वैश्विक विदेश नीति और प्रमुख आंतरिक सुधारों का विवरण इस प्रकार हैं-
एक, वैश्विक विदेश नीति: भारत प्रथम और बहु-ध्रुवीय कूटनीति: भारत की आधुनिक विदेश नीति को मोदी सिद्धांत (Modi Doctrine) के रूप में भी देखा जाता है। इसके मुख्य स्तंभ हैं- पड़ोस प्रथम नीति: दक्षिण एशिया में भारत की उपस्थिति और विश्वसनीयता को मजबूत करने के लिए बुनियादी ढांचे, बिजली और कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर विशेष ध्यान देना। एक्ट ईस्ट नीति: पूर्वी एशियाई और आसियान देशों के साथ आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को गहरा करना। ग्लोबल साउथ का नेतृत्व: विकासशील और गरीब देशों की प्राथमिकताओं (जैसे जलवायु न्याय, ऋण राहत और खाद्य सुरक्षा) को जी-20 जैसे मंचों पर उठाना।

रणनीतिक स्वायत्तता: किसी एक गुट में शामिल न होकर राष्ट्रहित के आधार पर अमेरिका, रूस, इजराइल और खाड़ी देशों के साथ स्वतंत्र संबंध बनाना। रणनीतिक स्वायत्तता: किसी एक गुट में शामिल न होकर राष्ट्रहित के आधार पर अमेरिका, रूस, इजराइल और खाड़ी देशों के साथ स्वतंत्र संबंध बनाना।

दो, प्रमुख आंतरिक सुधार: प्रशासनिक और आर्थिक कार्याकल्प के क्षेत्र, प्रमुख पहल, उसके प्रभाव और परिणाम

डिजिटल क्रांति: डिजिटल इंडिया (PI, Aadhaar, DigiLocker), भारत दुनिया का

सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान तंत्र बन गया; पारदर्शिता में वृद्धि करना।

कल्याणकारी तंत्र: डीबीटी (Direct Benefit Transfer) × जन धन योजना, बिचौलियों का खात्मा; करोड़ों रुपये की सीधे लाभार्थियों के खातों में डिलीवरी करना।

कर व आर्थिक सुधार: जीएसटी × आईबीसी, एक देश, एक कर व्यवस्था; व्यापार में सुगमता और डूबे हुए कर्जों (NPA) का समाधान करना।

संरचनात्मक विकास: पीएम गतिशक्ति × नेशनल इंफ्रा पाइपलाइन, राजमार्गों, रेलवे, बंदरगाहों और हवाई अड्डों का तेज गति से आधुनिकीकरण करना।

सुरक्षा और कानून : धारा 370 का समाप्ति × नया नागरिक न्याय कानून, जम्मू-कश्मीर का मुख्यधारा में एकीकरण; औपनिवेशिक कालीन आपराधिक कानूनों में सुधार करना।

आइए जानते हैं, भारतवासी प्रधानसेवक नरेंद्र मोदी को किस-किस रूप में देखते हैं?

एक, कड़े और मजबूत फैसले लेने वाले नेता (निर्णायक नेतृत्व): उनके समर्थक उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में देखते हैं जो राष्ट्रहित में बड़े और साहसिक फैसले लेने से पीछे नहीं हटते (जैसे- सर्जिकल स्ट्राइक, धारा 370 का हटना या बड़े आर्थिक सुधार)।

दो, विकास पुरुष और आधुनिक भारत के निर्माता: कई लोग उन्हें डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, बुनियादी ढांचे (हाईवे, बंदे भारत एक्सप्रेस, एयरपोर्ट) के विस्तार और आत्मनिर्भर भारत का विज़न देने वाले प्रशासक के रूप में देखते हैं।

तीन, कल्याणकारी योजनाओं के प्रदाता: देश का एक बड़ा गरीब और मध्यम वर्ग उन्हें उज्ज्वला

योजना, जनधन खाते, पीएम आवास योजना और मुफ्त राशन जैसी सीधी योजनाओं के माध्यम से उनके जीवन को आसान बनाने वाले संरक्षक के रूप में देखाता है।

चार, सांस्कृतिक पुनरुत्थान के प्रतीक: बहुसंख्यक समाज का एक वर्ग उन्हें हिंदू संस्कृति, परंपराओं और राष्ट्रीय गौरव को वैश्विक मंच पर पुनर्स्थापित करने वाले नेता के रूप में देखता है।

पांच, कठोर और केंद्रित प्रशासक (आलोचकों की नज़र में): आलोचक या विरोधी उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में देखते हैं जो केंद्रीकृत निर्णय लेते हैं और विपक्ष या मीडिया के साथ संवाद के सीमित अवसर देते हैं।

राजनीतिक विरोधी और अन्य नेता उनसे क्यों असहज रहते हैं?

विपक्षी नेताओं की चिढ़ या असहमति के पीछे मुख्य रूप से राजनीतिक, वैचारिक और रणनीतिक कारण हैं-

एक, चुनावी मशीनरी और अपराजित छवि मोदी का मजबूत संगठन (बीजेपी) और उनकी व्यक्तिगत जन-स्वीकार्यता विपक्षी दलों की पारंपरिक राजनीतिक और वोट बैंक को लगातार चुनौती देती है।

दो, सीधा जन-संवाद: मन की बात और सोशल मीडिया के माध्यम से मोदी जनता से बिना किसी बिचौलिए के सीधे जुड़ते हैं, जिससे पारंपरिक राजनीतिक बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाती है।

तीन, कठोर राजनीतिक और संस्थागत टकराव: विपक्ष का आरोप रहता है कि मोदी सरकार में केंद्रीय जांच एजेंसियों और प्रशासनिक तंत्र का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों पर दबाव बनाने के लिए किया जाता है।

चार, वैचारिक भिन्नता: कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय दल देश के धर्मनिपेक्ष ढांचे और समावेशी राजनीति के लिए उनकी हिंदुत्व आधारित विचारधारा को चुनौती मानते हैं।

बावजूद इसके पीएम नरेंद्र मोदी किसी से नहीं दबते। उन्होंने बहुत सही कार्य किए, लेकिन हिंदुत्व और जातिवाद को लेकर उनके मंत्रियों ने जो जो वैधानिक कुकृत्य किए, कराए, इससे उनका वह जनाधार दांव पर है, जिसने उन्हें हर हर मोदी, घर घर मोदी के रूप से सर्वस्वीकार्य बनाया। यदि इसकी काट वो दूढ़ लेते हैं तो एनडीए अपराजेय रहेगा, अन्यथा यूसीसी के बहाने बिहार से भगदड़ के संकेत मिलने लगे हैं।

गुस्सा आने पर तुरंत जवाब न दें, शांत रहना और नजरिया बदलना बेहतर उपाय

टॉम डेंसन

आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि रात में ठीक से नींद न आई हो, सुबह होते ही नाश्ते की मेज पर बच्चों से बहस हो गई ?हो, पड़ोसी ने गलत पार्किंग कर दी हो और दफ्तर पहुंचने में एक घंटे की देरी हुई हो। ऊपर से बाॅस ने ऐसा काम धमा दिया, जो लगभग नामुमकिन लग रहा हो। ऐसे में लोगों पर गुस्सा आना बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन, सवाल यह है कि गुस्सा आए, तो करें क्या? दौड़ने निकल जाएँ, सीढ़ियाँ चढ़ें या ध्यान लगाएं?

शोध बताते हैं कि हर तरीका गुस्सा कम नहीं करता। कुछ तरीके तो उल्टा उसे और भड़का सकते हैं। किसी भी दिन करीब 22 फीसदी लोग गुस्सा महसूस करते ही हैं। हालाँकि, ज्यादातर लोग इसे आक्रामक व्यवहार में नहीं बदलते, फिर



भी लगभग आठ फीसदी लोगों का मानना है कि गुस्सा उनकी जिंदगी पर नकारात्मक असर डालता ही है। आम धारणा है कि गुस्सा आने पर दौड़ना या सीढ़ियाँ चढ़ना अच्छा है। पर, शोध कुछ और ही कहते हैं। तेज शारीरिक गतिविधियाँ, खासकर दौड़ना या सीढ़ियाँ चढ़ना, कई बार गुस्से को और

बार बहस करना, सबक सिखाने की कल्पना करना या ‘उसने ऐसा किया ही क्यों?’ सोचते रहना गुस्से की आग में घी डाल सकता है। इसके बजाय, ध्यान भटकाना ज्यादा प्रभावी हो सकता है। इसके लिए, कोई किताब पढ़ें, शांत खेल खेलें या किसी सुखद याद को ताजा करें।

बढ़ा सकती हैं।

अच्छी बात यह है कि ज्यादातर मामलों में गुस्सा करीब 30 मिनट में स्वाभाविक रूप से कम होने लगता है। इसलिए, उस दौरान खुद को थोड़ा वक देना बेहतर है। बार-

मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। जरूरी नहीं और तुरंत उगल देना भी नहीं। ध्यान भटकाना, शांत रहना, माइंडफुलनेस और नजरिया बदलना न सिर्फ रिश्ते और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहतर है, बल्कि दिल की सेहत के लिए भी फायदेमंद हो सकते हैं। अगर गुस्सा बार-बार आता है, लंबे समय तक बना रहता है या आक्रामक व्यवहार में बदलने लगे, तो मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ की मदद लेना समझदारी भरा कदम है।

भारत की जमीन पर चीन के साथ मिलकर गुस्ताखी कर रहा था पाक

नीरज कुमार दुवे

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के संवेदनशील भूभाग को लेकर चीन और पाकिस्तान ने एक बार फिर ऐसी कवायद शुरू की है, जिस पर भारत ने कड़ा ऐतराज जताया है। पाकिस्तान और चीन द्वारा बनाए गए तथाकथित सीमा संयुक्त आयोग की पहली बैठक के बाद भारत ने साफ शब्दों में कहा है कि इस आयोग का कोई कानूनी आधार नहीं है और भारतीय भूभाग को लेकर पाकिस्तान को चीन के साथ किसी भी तरह की व्यवस्था करने का कोई अधिकार नहीं है। भारत ने दो टूक कहा है कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अविभाज्य हिस्से हैं तथा कब्जे वाले भारतीय क्षेत्रों को लेकर चीन-पाकिस्तान की कोई भी गतिविधि भारत की संप्रभुता पर प्रभावित नहीं कर सकती।

हम आपको बता दें कि इस आयोग की पहली बैठक इस्लामाबाद में हुई। पाकिस्तान ने इसे द्विपक्षीय संबंधों की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए सीमा प्रबंधन, संयुक्त सीमा सर्वेक्षण, व्यापारिक प्रवाह और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने की बात कही। बैठक की सह-अध्यक्षता चीन के विदेश मंत्रालय के सीमा एवं महासगरियी मामलों से जुड़े अधिकारी ली या और पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय में चीन मामलों के महानिदेशक बिलाल महमूद चौधरी ने की।

उधर, भारत ने इस पहल को महज दो देशों के बीच सामान्य सीमा सहयोग मानने से साफ इंकार कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन और पाकिस्तान के बीच ऐसी कोई सीमा नहीं है, जिसे भारतीय भूभाग के संदर्भ में दोनों देश मिलकर वैध रूप दे सकें। भारत ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्रशासित क्षेत्रों को अपना अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा बताते हुए कहा कि पाकिस्तान को अपने अवैध और बलपूर्वक कब्जे वाले भारतीय क्षेत्रों के बारे में किसी व्यवस्था में प्रवेश करने का अधिकार नहीं है।

देखा जाये तो इस पूरे घटनाक्रम की जड़ 1963 में हुए चीन-पाकिस्तान सीमा समझौते तक जाती है।



उस समझौते के तहत पाकिस्तान ने शक्सगाम घाटी के लगभग 5,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को चीन के साथ सीमा निर्धारण की व्यवस्था में शामिल किया था। हालांकि भारत ने इसे कभी मान्यता नहीं दी। भारत सरकार ने संसद में भी स्पष्ट किया है कि वह इस तथाकथित समझौते को अवैध और अमान्य मानती है तथा शक्सगाम घाटी को भारतीय क्षेत्र मानती है।

इसका इतिहास 1947-48 के भारत-पाकिस्तान युद्ध और तत्कालीन जम्मू-कश्मीर रियासत की स्थिति से जुड़ता है। भारत का आधिकारिक रुख है कि पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर के कुछ हिस्सों पर कब्जा किया और बाद में उसी क्षेत्र से चीन के साथ समझौता किया। इसलिए पाकिस्तान द्वारा उस भूभाग के संबंध में चीन के साथ कोई भी समझौता अपने आप में अधिकारहीन है।

हम आपको बता दें कि शक्सगाम घाटी और कराकोरम केवल मानचित्र पर दिखाई देने वाली दूरस्थ पहाड़ी जमीन नहीं हैं। यह इलाका चीन के शिनच्यांग क्षेत्र, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और लद्दाख के बीच स्थित अत्यंत संवेदनशील पर्वतीय क्षेत्र है। इसी व्यापक भूभाग में चीन-पाकिस्तान संपर्क की महत्वपूर्ण आधारभूत संरचनाएं विकसित हुई हैं। चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का एक हिस्सा भी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है, जिस पर भारत लगातार आपत्ति जताता रहा है।

रणनीतिक दृष्टि से इसका महत्व इसलिए और

आज का इतिहास

- 1891 विलियम शेक्सपीयर के प्रसिद्ध नाटक मचैट ऑफ वेनिस का मैनचेस्टर में पहली बार मंचन किया गया।
- 1893 स्वामी विवेकानंद ने शिकागो (अमेरिका) के विश्व धर्मसंसद में ऐतिहासिक भाषण दिया।
- 1893 न्यूजीलैंड में निर्वाचन अधिनियम 1893 के तहत सभी महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया।
- 1955 अर्जेंटीना की सेना और नौसेना ने विद्रोह कर राष्ट्रपति जुआन पेरोन को पद से हटाया।
- 1957 अमेरिका ने नेवादा के रेिंगस्तान में पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण किया।
- 1962 भारत की उत्तरी सीमा पर चीन द्वारा आक्रमण।
- 1982 स्कॉट फाहमैन ऑनलाइन संदेश का इस्तेमाल करने वाले पहले व्यक्ति बने।
- 1983 ब्रिटिश उपनिवेश कैरीबियन द्वीप, सेंट किट्स एवं नेविस स्वतंत्र।
- 1988 इस्त्राएल ने परीक्षण उपग्रह होरिजोन-आई का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया।
- 1996 एलिका इजेन्बोगोविक युद्धोत्तरकालीन बोस्निया के प्रथम राष्ट्रपति बने।
- 1996 इस्त्रायल और वामपंथी विद्रोहियों की सरकार ने लंबे समय से चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए एक शांति संधि पर हस्ताक्षर किए।
- 2000 कर्नम मल्लेश्वरी ने ओलंपिक में भारोत्तोलन स्पर्धा में कांस्य पदक जीता।
- 2002 इस्त्रायल के सैनिकों ने पश्चिमी किनारे पर फ़िलिस्तीन नेता यासिर अराफ़ात की घेराबंदी की।
- 2006 सरकार का तख्ता पलटने के बीच थाइलैंड में इमरजेंसी लागू। पोप बेंनेडिक्ट ने अपनी इस्लाम सम्बन्धी टिप्पणी के लिए माफ़ी मांगी। उत्तर कोरिया के ख़ुलाफ़ आर्थिक प्रतिबंध को जापान ने मंजूरी प्रदान की। भारत ने आई.एम.एफ़. से सहयोग का वायदा किया।
- 2006 थाईलैंड में सैन्य तख्तापलट, जनरल सुरायुद प्रधानमंत्री बने।
- 2008 सर्वोच्च न्यायालय ने छत्तीसगढ़ में नक्सली गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए शुरू किए गये शलवाजुइयूम के कार्यकर्ताओं की गतिविधियों को बंद करने का निर्देश दिया।
- 2009 गुजरात के गोधरा काण्ड के बाद भड़के दंगे की मामले की जाँच कर रहे नानावती आयोग ने राज्य में मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा छह अन्य लोगों को तलब करने की मांग वाली याचिका का निबटारा किया।

सेमीकॉन इंडिया 26 सिलिकॉन से सिस्टम तक विकसित भारत 2047 की नई उड़ान

विनोद सिंह ‘तकियावाला’

वैश्विक मानचित्र पर किसी देश की आर्थिक शक्ति का आकलन केवल उसकी सड़कों,रेल लाइनों, बंदरगाहों,गगनचुंबी इमारतों या डिजिटल नेटवर्क से नहीं होता। बल्कि आज के बदलते परिवेश में उस देश की असली ताकत इस बात से भी तय होती है कि वह नवीन तकनीकों का निर्माण कितना कर सकता है,जो इन सभी व्यवस्थाओं को संचालित करती हैं।आज की डिजिटल अर्थव्यवस्था में सेमीकंडक्टर ऐसी ही बुनियादी तकनीक बन चुका है।मोबाइल फोन से लेकर रेलवे, ऑटोमोबाइल,कृत्रिम बुद्धिमत्ता, चिकित्सा उपकरण,रक्षा प्रणाली, अंतरिक्ष तकनीक और डेटा सेंटर तक शायद ही कोई आधुनिक क्षेत्र हो,जिसकी कार्यप्रणाली चिप के बिना पूरी हो सके।इसी बदलती वैश्विक तकनीकी व्यवस्था के बीच नई दिल्ली का यशोभूमि इन दिनों केवल एक प्रदर्शनी स्थल नहीं,बल्कि भारत की भावी आर्थिक और तकनीकी दिशा का साक्षी बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर को सेमीकॉन इंडिया 2026 के पाँचवें संस्करण का उद्घाटन किया। 17 से 19 सितंबर तक चलने वाले इस इ सेमीकॉन इंडिया 2026 का विषय है—सिलिकॉन से सिस्टम तक = इकोसिस्टम का निर्माण। 52 देशों की भागीदारी, 600 से अधिक प्रदर्शक,150 से अधिक वक्ता छह देश मंडप और 12 राज्य मंडप इस आयोजन को वैश्विक तकनीकी संवाद का महत्वपूर्ण मंच बना रहे हैं। सर्व विदित रहे कि सेमीकॉन इंडिया 2026 का महत्व केवल इसकी भव्यता और वैश्विक भागीदारी में नहीं है।इसका वास्तविक महत्व उस परिवर्तन में छिपा है,जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने अपने उद्घाटन संबोधन में रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि

भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा अब परियोजनाओं की घोषणा और निर्माण के चरण से आगे बढ़कर वाणिज्यिक उत्पादन तक पहुँच गई है।उनके अनुसार पहले सेमीकॉन आयोजन में नीतियों पर चर्चा हुई,फिर परियोजनाओं और शिलान्यास की बात आई,पिछले वर्ष पायलट लाइन और टेस्ट चिप की चर्चा हुई और अब भारतीय संयंत्रों से तैयार चिप ग्राहकों तक पहुँचने लगी है।यही बदलाव विकसित भारत 2047 की बड़ी तस्वीर को समझने की कुंजी भी है।भारत ने लंबे समय तक इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में मुख्यतः उपभोक्ता बाजार के रूप में अपनी पहचान बनाई। मोबाइल फोन से लेकर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों तक भारत में खपत तेजी से बढ़ी,लेकिन उसके पीछे लगने वाली चिप तकनीक का बड़ा हिस्सा बाहर से आता रहा।आज तस्वीर बदलने की कोशिश हो रही है।अब लक्ष्य केवल चिप का इस्तेमाल करना नहीं,बल्कि उसके डिजाइन से लेकर निर्माण,पैकेजिंग, परीक्षण, उपकरण,सामग्री और अंततः चिप से तैयार सिस्टम तक पूरी मूल्य श्रृंखला को भारत में मजबूत करना है।इसीलिए इस वर्ष का सिलिकॉन से सिस्टम तक विषय अपने भीतर एक बड़ी आर्थिक कहानी समेटे हुए है।यशोभूमि में प्रदर्शित ‘सैंड से सिलिकॉन से सिस्टम’ मूल्य श्रृंखला यह दिखाती है कि भारत की महत्वाकांक्षा केवल किसी एक फैब्र या पैकेजिंग इकाई तक सीमित नहीं है।लक्ष्य एक ऐसा व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना है,जिसमें डिजाइनर, इंजीनियर,निर्माता,उपकरण कंपनियाँ,कच्चे माल के उत्पादक, शोध संस्थान,स्टार्टअप और अंतिम इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली बनाने वाली कंपनियाँ—एक-दूसरे से जुड़े।यहीं से विकसित भारत 2047 का सपना सेमीकॉन



इंडिया 2026 से जुड़ता है।

2047 में भारत अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी मनाएगा।उस समय भारत की अर्थव्यवस्था कैसी होगी, उसकी वैश्विक तकनीकी भूमिका क्या होगी और उसके युवाओं के पास किस प्रकार के रोजगार होंगे,इन प्रश्नों के उत्तर आज की नीतियों और निवेश से तैयार होंगे।सेमीकंडक्टर क्षेत्र इस भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह केवल एक उद्योग नहीं,बल्कि अनेक उद्योगों की आधारभूत तकनीक है।प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में भारत की इस यात्रा को नई गति मिलने की बात कही और यह भी रेखांकित किया कि भारत ने कुछ ही वर्षों में वह प्रगति की है,जिसमें सामान्यतः अधिक लंबा समय लगता है। उन्होंने भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा को दूसरे चरण में प्रवेश करने वाला बताया।साथ ही उन्होंने उद्योग जगत से अनुसंधान एवं विकास में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया और भारत तथा विदेशों में शोध कर रहे युवा वैज्ञानिकों और प्रतिभाओं को देश की उन्नत तकनीकी यात्रा से जुड़ने का आग्रह किया।युवा इंजीनियर इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण अस्थाय हैं।सेमीकंडक्टर उद्योग में केवल पूंजी लगाने से

कारखाना खड़ा नहीं होता। इसके लिए डिजाइन इंजीनियर, माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स विशेषज्ञ, सामग्री वैज्ञानिक,उपकरण इंजीनियर, सॉफ्टवेयर विशेषज्ञ, पैकेजिंग विशेषज्ञ,परीक्षण विशेषज्ञ और अनुसंधानकर्ता चाहिए।यही कारण है कि सेमीकॉन इंडिया 2026 में वर्कफोर्स डेवलपमेंट पवेलियन और छात्र हैकथॉन जैसे कार्यक्रमों को भी स्थान दिया गया है।लगभग 40 स्टार्टअप वाला स्टार्टअप पवेलियन भी यह संदेश देता है कि भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा केवल बड़ी कंपनियों की कहानी नहीं है।

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में युवाओं को चिप डिजाइन का प्रशिक्षण दिए जाने और उन्हें स्वयं चिप डिजाइन करने के अवसर मिलने की चर्चा की।यह बदलाव बहुत महत्वपूर्ण है। इंजीनियरिंग की शिक्षा अब केवल डिग्री प्राप्त करने तक सीमित नहीं रह सकती।भारत को ऐसे इंजीनियर चाहिए जो समस्या को समझें,डिजाइन तैयार करें, प्रयोग करें,असफल हों और फिर नया समाधान विकसित करें। प्रयोगशाला से उद्योग और उद्योग से बाजार तक जाने वाली यही संस्कृति विकसित भारत की तकनीकी नींव बनेगी।सेमीकॉन 2.0 इसी दिशा में अगला कदम है।इस कार्यक्रम का जोर केवल बड़े सिलिकॉन फैब्र पर नहीं, बल्कि डिजाइन,विशेषीकृत फैब्र, उन्नत पैकेजिंग,उपकरण एवं घटक निर्माण,कच्चे माल, अनुसंधान एवं विकास तथा प्रतिभा निर्माण जैसे क्षेत्रों पर है। यानी सरकार अब पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने की दिशा में बढ़ रही है। कार्यक्रम में चिप डिजाइन, उपकरण और सामग्री से लेकर अनुसंधान और कौशल

तक अनेक स्तरों को समर्थन देने की व्यवस्था की गई है।इसका सीधा संबंध भारत की अर्थव्यवस्था से है।भारत को यदि 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था बनना है तो उसे उच्च मूल्य वाले विनिर्माण में अपनी हिस्सेदारी बढ़ानी होगी। सेवा क्षेत्र ने भारत को वैश्विक पहचान दी है,लेकिन आने वाले समय में विनिर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स,सेमीकंडक्टर, रक्षा उत्पादन,हरित ऊर्जा,अंतरिक्ष और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे क्षेत्र आर्थिक विकास के नए इंजन बन सकते हैं।सेमीकंडक्टर इन सभी क्षेत्रों के बीच एक साड़ा कड़ो है।

एक चिप केवल एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक घटक नहीं है। इसके पीछे डिजाइन सॉफ्टवेयर से लेकर अत्यंत शुद्ध सामग्री,विशेष मशीनें,रसायन, गैसों, परीक्षण प्रयोगशालाएँ, पैकेजिंग तकनीक और प्रशिक्षित मानव संसाधन की पूरी श्रृंखला होती है।इसलिए भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग का विस्तार होने का अर्थ हजारों प्रत्यक्ष नौकरियों के साथ उससे जुड़े अनेक सहायक उद्योगों, सेवाओं और आपूर्ति श्रृंखलाओं का विकास भी है।इसीलिए सेमीकॉन इंडिया 2026 को रोजगार और युवा उद्यमिता के दृष्टिकोण से भी देखना आवश्यक है।अतीत के आने वाले वर्षों में चिप डिजाइन,एम्बेडेड सिस्टम, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, इलेक्ट्रिक वाहन, डेटा सेंटर और स्मार्ट विनिर्माण के क्षेत्र में नई विशेषज्ञता की मांग बढ़ेगी।भारत के इंजीनियरिंग संस्थानों के सामने यह अवसर है कि वे अपने पाठ्यक्रम और प्रयोगशालाओं को भविष्य की इन जरूरतों से जोड़ें।प्रधानमंत्री ने उद्योग से अनुसंधान एवं विकास की जिम्मेदारी अधिक सक्रियता से लेने का आह्वान भी इसी संदर्भ में किया।

विपक्ष में बढ़ते मदभेदों के बीच तीसरे मोर्चे की तैयारी?

राहुल कुमार

विपक्षी खेमे में बढ़ते मतभेदों के बीच राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। डीएमके की वरिष्ठ नेता कनिमोझी ने कोलकाता में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी से उनके आवास पर बंद कमरे में मुलाकात की। इससे पहले कनिमोझी उड़व ठाकरे और शरद पवार से भी चर्चा कर चुकी हैं। ऐसे में इन क्षेत्रीय दलों के बीच बढ़ते संपर्क को लेकर सियासी गलियारों में नए राजनीतिक समीकरणों की अटकलें तेज हो गई हैं। डीएमके की वरिष्ठ नेता कनिमोझी ने गुरुवार को कोलकाता में पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। दोनों के बीच यह बैठक दक्षिण कोलकाता के कालीघाट स्थित ममता के आवास पर हुई।टीएमसी के एक नेता ने बताया कि लोकसभा सांसद कनिमोझी ने ममता के साथ उनके आवास पर बंद कमरे में बैठक की। उन्होंने कहा, कनिमोझी और ममता बनर्जी के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। कनिमोझी की ममता से यह मुलाकात मुंबई में शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे और दिल्ली में पनसीपी (एसपी) प्रमुख शरद पवार के साथ चर्चा के कुछ दिनों बाद हुई है। डीएमके और कांग्रेस के बीच तनाव तथा विपक्षी इंडिया गठबंधन के कई क्षेत्रीय सहयोगियों के बीच मतभेदों के बीच कनिमोझी का यह संपर्क चर्चा में है। टीएमसी और कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में दोनों दलों के रिस्ते तनावपूर्ण रहे हैं। हाल ही में छह अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव को लेकर भी दोनों पार्टियों के बीच तनातनी सामने आई है। राज्य कांग्रेस ने दावा किया था कि टीएमसी ने



नंदीग्राम सीट उसके लिए छोड़ने के प्रस्ताव के साथ केंद्रीय नेतृत्व से संपर्क किया था। हालांकि, ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट ने इस दावे को खारिज कर दिया। उधर तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के बाद डीएमके और कांग्रेस के रिश्तों में भी तनाव आया है। कांग्रेस अब अभिनेता से नेता बने सी. जोसेफ विजय की टीवीके के नेतृत्व वाले सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा है, जबकि डीएमके विपक्ष में है। डीएमके ने जून में इंडिया गठबंधन की बैठक में हिस्सा नहीं लिया था। इसके बाद से पार्टी ने कांग्रेस के प्रति अधिक टकराव वाला रुख अपनाया है। इस पृष्ठभूमि में कनिमोझी की बैठकों ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले ढांचे से बाहर की पार्टियों के बीच तालमेल मजबूत करने के प्रयासों को लेकर अटकलों को जन्म दिया है। हालांकि, अभी ऐसा कोई आधिकारिक संकेत नहीं है कि इन चर्चाओं का उद्देश्य कोई नया राजनीतिक समूह बनाना था। टीएमसी भी राजनीतिक उथल-पुथल के दौर से गुजर रही है। पश्चिम बंगाल में भाजपा के सत्ता में आने के बाद उसका 15 साल का शासन खत्म हो गया है। पार्टी को राज्य विधानसभा के साथ-साथ अपने संसदीय सदस्यों के बीच भी असंतोष का सामना करना पड़ रहा है।

सत्येंद्र प्रताप सिंह

पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस का सफर 1998 से शुरू हुआ था। कांग्रेस से अलग होकर ममता बनर्जी ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी बनाई। पार्टी को उसका नाम और चुनाव चिन्ह मिला और उसी साल लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस पहली बार मैदान में उतरी। यही वह दौर था जब ममता बनर्जी ने बंगाल को तृणमूल में कांग्रेस से अलग अपनी स्वतंत्र पहचान बनाने की कोशिश शुरू की। 1998 के लोकसभा चुनाव से लेकर आगे के हर चुनाव में ‘ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस’ और उसका पारंपरिक चुनाव चिन्ह पार्टी की पहचान बन गया।

करीब तीन दशक तक बंगाल के मतदाताओं ने तृणमूल को इसी नाम और इसी निशान के साथ देखा। चुनावी पोस्टर से लेकर ईवीएम तक यहीं पहचान पार्टी और उसके उम्मीदवारों को बाकी दलों से अलग करती रही। अब इसी कहानी में एक ऐसा मोड़ आया है, जिसकी कल्पना शायद तृणमूल की स्थापना के समय किसी ने नहीं की होगी। 1998 में जिस नाम और चुनाव चिन्ह के साथ पार्टी ने अपनी चुनावी यात्रा शुरू की थी, 2026 में उसी मूल नाम और निशान के साथ चुनाव लड़ने की स्थिति फिलहाल नहीं है।

चुनाव आयोग के अंतरिम फैसले के बाद दोनों गुट तृणमूल कांग्रेस के मूल नाम और पारंपरिक चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। दोनों पक्षों से नए नाम और मुक्त चुनाव चिन्ह के विकल्प मांगे गए हैं। यानी 1998 के बाद पहली बार ऐसा होगा जब बंगाल के चुनाव में तृणमूल की वह



मूल पहचान मतदाताओं के सामने नहीं होगी, जिसे पिछले 28 वर्षों में पार्टी ने लगातार मजबूत किया है। तृणमूल कांग्रेस के सामने यह संकेत केवल चुनाव चिन्ह तक सीमित नहीं है। बंगाल की सत्ता में बदलाव के बाद पार्टी के भीतर भी बड़ा विभाजन सामने आया है। विधायक और सांसद अलग-अलग खेमों में दिखाई दे रहे हैं और पार्टी के संगठनात्मक नियंत्रण को लेकर दोनों पक्षों के दावे सामने हैं।

यानी एक तरफ सत्ता जाने का राजनीतिक झटका है, दूसरी तरफ संगठन में टूट और अब तीसरी चुनौती पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह की है। किसी राजनीतिक दल के लिए नाम और निशान महज प्रशासनिक औपचारिकता नहीं होते। वर्षों तक एक ही पहचान के साथ चुनाव लड़ने के बाद वही निशान मतदाताओं के लिए पार्टी की पहचान बन जाता है। ऐसे में अचानक नाम और चुनाव चिन्ह बदलना केवल कागज पर बदलाव नहीं, बल्कि चुनावी पहचान में बड़ा परिवर्तन है।

पूरे विवाद का सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर मूल तृणमूल कांग्रेस के नाम और चुनाव चिन्ह पर दावा किसका स्वीकार किया जाएगा। दोनों गुट अपने-अपने पक्ष में

दावे और दस्तावेज पेश कर रहे हैं। चुनाव आयोग के सामने यह सवाल है कि पार्टी की वैध संगठनात्मक पहचान और उसके प्रतिनिधित्व का अधिकार किस पक्ष के पास है। फिलहाल आयोग ने किसी एक गुट को मूल नाम और निशान सौंपने के बजाय दोनों के इस्तेमाल पर रोक लगाई है। यह अंतरिम व्यवस्था है। इसलिए अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि तृणमूल का मूल नाम और चुनाव चिन्ह हमेशा के लिए खत्म हो गया। अंतिम फैसला आगे की प्रक्रिया के बाद ही तस्वीर साफ करेगा।

सबसे तत्काल असर आगामी उपचुनावों पर दिखाई देगा।दोनों गुटों को अलग-अलग नाम और चुनाव चिन्ह के साथ मैदान में उतरना होगा। यह स्थिति तृणमूल के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसके सामने पहली बार अपने पुराने चुनावी ब्रांड के बिना मतदाताओं तक पहुँचने की चुनौती होगी। अब उम्मीदवार का नाम, स्थानीय संगठन और व्यक्तिगत राजनीतिक पहचान पहले की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है। मतदाताओं को यह समझाना भी जरूरी होगा कि नया नाम और नया निशान किस गुट का प्रतिनिधित्व करता है।

ममता बनर्जी की राजनीति की एक बड़ी विशेषता उनकी व्यक्तिगत राजनीतिक पहचान रही है। लेकिन चुनावी राजनीति में व्यक्तिगत पहचान के साथ पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 1998 से लगातार जिस नाम और निशान के साथ चुनाव लड़ा गया, उसके

अचानक सामने न होने की स्थिति निश्चित तौर पर तृणमूल के लिए एक नया राजनीतिक अध्याय है।

ममता बनर्जी के सामने अब सवाल केवल यह नहीं होगा कि कितनी सीटों पर उम्मीदवार उतारे जाएँ या संगठन को कैसे मजबूत किया जाए। सवाल यह भी होगा कि पुराने समर्थकों के बीच नई चुनावी पहचान को कैसे स्थापित किया जाए।

यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल है। क्या 28 साल पुराना तृणमूल का नाम और चुनाव चिन्ह किसी एक गुट को फिर मिल पाएगा? या फिर दोनों पक्षों को लंबे समय तक अलग-अलग राजनीतिक पहचान के साथ आगे बढ़ना होगा? फिलहाल इसका जवाब नहीं है। चुनाव आयोग का मौजूदा फैसला अंतरिम है और अंतिम फैसला अभी बाकी है।

इसलिए इसे तृणमूल की राजनीतिक पहचान का अंत कहना सही नहीं होगा। लेकिन इतना जरूर है कि 1998 में जिस नाम और निशान से शुरू हुई तृणमूल की चुनावी यात्रा, 2026 में पहली बार उस पहचान के बिना आगे बढ़ रही है।

सत्ता चली गई, विधायक-सांसद बंट गए और अब नाम-निशान भी विवाद में है। ऐसे में तृणमूल के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है—क्या ममता बनर्जी नई पहचान के साथ पुरानी तृणमूल को बचा पाएंगी, या 28 साल पुरानी राजनीतिक पहचान अब इतिहास का हिस्सा बनने जा रही है?

इस सवाल का पहला जवाब आगामी उपचुनाव देंगे, लेकिन अंतिम तस्वीर चुनाव आयोग के फैसले के बाद ही सामने आएगी।

हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक तेजी से एक्टिव हुआ भारत

नीरज कुमार दुबे

नई दिल्ली ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के तुरंत बाद जिस गति से पड़ोसी देशों के साथ उच्चस्तरीय संपर्क बढ़ाया है, उसने भारतीय विदेश नीति के अगले चरण की तस्वीर काफी हद तक साफ कर दी है। 12–13 सितंबर को नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के बाद भारत ने हिमालयी पड़ोस और हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी सक्रियता तेज कर दी है।

भूटान में विदेश मंत्री एस. जयशंकर की यात्रा इसका सबसे ताजा उदाहरण है। 16 से 18 सितंबर तक की यात्रा में जयशंकर ने भूटान के प्रधानमंत्री के अलावा विदेश मंत्री डी.एन. ढुंग्येल के साथ विकास, ऊर्जा, व्यापार, संपर्क, संस्कृति और दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों पर व्यापक चर्चा की। इसके साथ ही भारत ने तीन महत्वपूर्ण परियोजनाओं को आगे बढ़ाकर यह संदेश दिया कि भूटान के साथ संबंध केवल पारंपरिक मित्रता तक सीमित नहीं, बल्कि जमीन पर दिखाई देने वाले विकास और रणनीतिक सहयोग पर आधारित हैं। जयशंकर ने भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोबगे को 54 ‘मेड इन इंडिया’ इलेक्ट्रिक वाहन सौंपते हुए कहा कि मुझे बेवद खुशी हुई। उन्होंने कहा कि भारत, भूटान की ई-मोबिलिटी और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था की दिशा में हो रही प्रगति में सहयोग कर रहा है।

साथ ही गासा में 500 किलोवाट की तुलना जलविद्युत परियोजना की आधारशिला रखी गई। इसका उद्देश्य भूटान की उन बस्तियों तक बिजली पहुंचाना है, जो अब तक विद्युतीकरण से बाहर हैं। मोंगार में 65 बिस्तरों वाले ग्यालत्सुएन जेत्सुन पेमा मातृ एवं शिशु अस्पताल का उद्घाटन हुआ, जबकि समदृष जोंगखार में 80 मीटर लंबे जलान्तर पुल का लोकार्पण किया गया। ऊर्जा, स्वास्थ्य और सड़क संपर्क, तीनों क्षेत्रों में एक साथ आगे बढ़ाए गए ये काम भारत-भूटान साझेदारी की व्यापकता दिखाते हैं।

इसके अलावा, भूटान के बूमथांग में जयशंकर की गतिविधियों का एक मानवीय पक्ष भी सामने आया। उन्होंने स्थानीय किसानों के लिए शुद्ध नस्ल की 43 जर्सी गायें सौंपीं। उनका कहना था कि इससे भूटान के डेयरी कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी, दूध उत्पादन बढ़ेगा और किसानों की आय को लाभ होगा। उन्होंने वांगदुएछोलिंग महल और



संग्रहालय का दौरा किया तथा कुर्जे ल्हाखांग में प्रार्थना भी की। इससे यह संकेत मिलता है कि भारत का भूटान संपर्क केवल सरकारी समझौतों तक सीमित नहीं, बल्कि कृषि, संस्कृति और जनसंपर्क तक फैला हुआ है। साथ ही जयशंकर की यात्रा को विदेश सचिव विक्रम मिसरा की हाल की भूटान यात्रा से अलग करके नहीं देखा जा सकता। 30–31 जुलाई को मिसरा ने भूटान के विदेश सचिव पेमा लेकुप दोर्जी के साथ 13वीं पंचवर्षीय योजना के लिए पांचवीं भारत-भूटान विकास सहयोग वार्ता की सह-अध्यक्षता की थी। दोनों देशों ने विकास साझेदारी, ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की थी। भूटान की 2024–29 की पंचवर्षीय योजना के लिए भारत के 10,000 करोड़ रुपये के समर्थन की प्रगति की भी समीक्षा हुई थी। नएस्थान तलाशें

अर्थात जुलाई में विदेश सचिव स्तर पर बनी रूपरेखा के बाद सितंबर में विदेश मंत्री स्तर पर उसके राजनीतिक और व्यावहारिक आयामों को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसे भारत की भूटान नीति में निरंतरता और संस्थागत गहराई के संकेत के रूप में देखा जा सकता है। इस बीच नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वाले आल 17 सितंबर को नई दिल्ली पहुंचे हैं। उनकी यात्रा का मुख्य केंद्र हाल की विनाशकारी बाढ़ के बाद नेपाल के पुर्ननिर्माण, आर्थिक सहयोग और ऊर्जा संबंधी जरूरतें हैं। वह भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री जयशंकर सहित अन्य अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। भारत ने संकट की घड़ी में नेपाल को बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में भी कदम उठाया है। भारत ने दिसंबर के अंत तक नेपाल को प्रतिदिन 18 घंटे के लिए 654 मेगावाट तक बिजली निर्यात की अनुमति दी है। उल्लेखनीय है कि बाढ़ से नेपाल की जलविद्युत परियोजनाओं और बुनियादी ढांचे को भारी

नुकसान हुआ है। इसके अलावा, दक्षिण दिशा में भी भारत ने समानांतर संदेश दिया है। 8 से 10 सितंबर के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीलंका की यात्रा की, जो लगभग 38 वर्षों बाद किसी भारतीय रक्षा मंत्री की श्रीलंका यात्रा थी। दोनों देशों ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता पर सहयोग बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने स्पष्ट किया कि श्रीलंकाई भूभाग का इस्तेमाल भारत की सुरक्षा के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए नहीं होने दिया जाएगा।

इन घटनाओं को एक साथ रखकर देखें तो भारत की रणनीति के तीन स्पष्ट आयाम सामने आते हैं। हिमालय में विकास और संपर्क, आपदा के समय आर्थिक तथा मानवीय सहयोग और हिंद महासागर में सुरक्षा साझेदारी। देखा जाये तो भूटान में जलविद्युत और पुल, नेपाल में पुर्ननिर्माण और बिजली तथा श्रीलंका में रक्षा और समुद्री सुरक्षा, ये सब भले अलग-अलग पहल दिखती हैं, लेकिन इनके पीछे क्षेत्रीय स्थिरता और भारत-केंद्रित संपर्क तंत्र को मजबूत करने की साझा दिशा दिखाई देती है। सामरिक दृष्टि से भूटान का महत्व विशेष है। भारत-भूटान सीमा और हिमालयी क्षेत्र चीन के साथ भारत की व्यापक सुरक्षा गणना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे में भूटान के साथ विश्वास, संपर्क, ऊर्जा और विकास सहयोग को मजबूत करना केवल आर्थिक साझेदारी नहीं, बल्कि दीर्घकालिक सामरिक स्थिरता से भी जुड़ा है। वहीं नेपाल भारत की उत्तरी सुरक्षा और संपर्क संरचना में महत्वपूर्ण है, जबकि श्रीलंका हिंद महासागर में समुद्री मार्गों और क्षेत्रीय सुरक्षा की दृष्टि से अहम है। इसलिए काठमांडू, थिम्पू और कोलंबो में एक साथ सक्रियता को भारत के पड़ोस को अलग-अलग द्विपक्षीय रिश्तों की बजाय एक जुड़े हुए क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में देखने की कोशिश के रूप में समझा जा सकता है।

बहरहाल, ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने की बात करने के तुरंत बाद पड़ोस में विकास, पुर्ननिर्माण, ऊर्जा, संपर्क और सुरक्षा पर जोर देकर भारत यह दिखा रहा है कि उसकी वैश्विक भूमिका का आधार केवल बड़े अंतरराष्ट्रीय मंच नहीं, बल्कि उसके आसपास का स्थिर, जुड़ा और सहयोगी क्षेत्र भी है। यही इस पूरी कूटनीतिक सक्रियता का सबसे बड़ा रणनीतिक संकेत है।

महिला वोटरों के लिए मुफ्त योजनाओं की होड़

कनिका दत्ता

भारत की महिलाओं, विशेषकर गरीबी रेखा के आसपास रहने वाली महिलाओं की स्थिति इतनी अच्छी कभी नहीं रही। पिछले कई वर्षों से बढ़ती संख्या में राजनीतिक दलों ने उन्हें चुनावी प्रक्रिया का एक संभावित लाभदायक पहलू मान लिया है। उत्तर भारत में, बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने 2016 में राज्य में शराबबंदी लागू करके इस समझ का भरपूर लाभ उठाया। लेकिन चुनावी मुकाबले में आम तौर पर मुफ्त वार्दों से परिभाषित होते जा रहे हैं। 2026 की शुरुआत में हुए पांच विधान सभा चुनावों में पार्टियों ने महिला-लक्षित कल्याणकारी योजनाओं के लिए जमकर प्रतियर्धा की। इसमें कोई संदेह नहीं है कि नकद सहायता प्राप्त करने वाली महिला लाभार्थियों ने अप्रत्याशित लाभों का भरपूर आनंद उठाया है। उद्धे संबंधित पार्टी को वोट देने पर और अधिक मदद का वादा किया गया। लेकिन महिला कल्याण योजनाओं और चुनाव परिणामों के बीच सीधा संबंध स्पष्ट नहीं है। बिहार को छोड़कर, जहां महिला-केंद्रित नीतियों और चुनावी परिणामों के बीच एक मजबूत संबंध दिखाई देता है, विशेष रूप से 2015 के चुनावों में, अन्य जगहों पर परिणाम एक जैसे नहीं रहे हैं। उदाहरण के लिए, तमिलनाडु में द्रविड़ मुन्नेत्र कण्मम ने राज्य की महिला मतदाताओं पर खूब पैसा और मुफ्त सुविधाएं लुटाईं, लेकिन एक अभिनेता और राजनीति में नौसिखिए द्वारा शुरू की गई पार्टी की लोकप्रियता के आगे यह पार्टी टिक नहीं पाई। इससे साफ संदेश मिलता है- महिलाओं को भी आम लोगों की तरह ही आर्थिक सहायता अच्छी लगती है, लेकिन उनके वोट सार्थक राजनीतिक कार्यक्रमों पर निर्भर करते हैं। दरअसल, मुफ्त योजनाओं के इस उन्माद की असली परीक्षा तो यही होनी चाहिए। क्या ये सहायता राशि महिलाओं के जीवन को स्थायी और व्यावहारिक रूप से बेहतर बना सकती है, या फिर ये मतदाताओं के एक कमजोर वर्ग का एक स्वार्थपूर्ण और अस्थायी शोषण मात्र हैं? कुल मिलाकर, कोई निश्चित पैटर्न स्थापित करना कठिन है। उदाहरण के लिए, पश्चिम बंगाल में आर्थिक

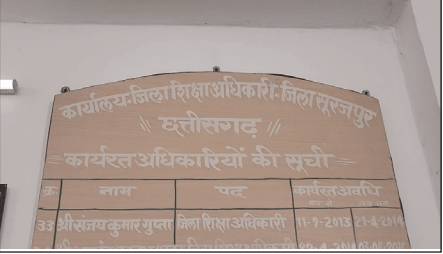
रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए ममता बनर्जी की लक्ष्मी भंडार योजना को ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी पार्टी के मजबूत प्रदर्शन का एक कारण माना गया। लेकिन यह महिलाओं पर हिंसा के प्रति उनकी चौंकाने वाली उदासीनता और यौन उत्पीड़न पीड़ितों के प्रति विद्वेष के बिल्कुल विपरीत है। लगभग हर क्षेत्र में उनके अनियमित शासन के साथ-साथ, इसने भारतीय जनता पार्टी से उनकी पराजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सच्चाई यह है कि लक्षित मुफ्त योजनाओं को महिला सशक्तीकरण का मुख्य साधन माना जा रहा है, लेकिन महिलाओं की स्थिति में बदलाव लाने में इनका प्रभाव नगण्य है। तमिलनाडु में महिलाएं उत्तर प्रदेश या उत्तरी भारत के लगभग हर हिस्से की तुलना में अधिक शिक्षित, आर्थिक रूप से अधिक स्वतंत्र और अधिक सशक्त अधिकारों की धनी हैं। लेकिन यह लक्षित मुफ्त योजनाओं का परिणाम कम और राज्य में हाल तक सत्ता में रहे दो प्रमुख दलों द्वारा अपनाए गए सार्वभौमिक सामाजिक न्याय वितरण मॉडल का परिणाम अधिक है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि भारतीय राय्यों में महिला कारखाना श्रमिकों का अनुपात सबसे अधिक तमिलनाडु में है। बिहार में अध्ययनों से पता चलता है कि शराबबंदी के परिणामस्वरूप घरेलू हिंसा और महिलाओं के खिलाफ अपराधों में भारी कमी आई है। महिलाओं ने शराब से होने वाली बचत का महत्व समझा है जिससे बच्चों की शिक्षा आदि के लिए उपलब्ध घरेलू बजट में वृद्धि हुई। अजीब बात यह है कि दहेज हत्याओं में यह कमी परिलक्षित नहीं होती है, बल्कि इसके विपरीत, 2016 के बाद दहेज हत्याओं में वृद्धि हुई है। यह दर्शाता है कि महिलाएं अभी भी उस मानसिकता में फंसी हुई हैं जहां समाज उन्हें स्वतंत्र मानव के रूप में नहीं बल्कि अवसरवादी आर्थिक शोषण की इकाई के रूप में देखता है। दूसरी ओर, महिलाओं से अब भी समाज द्वारा निर्धारित सामाजिक भूमिकाओं को निभाने की अपेक्षा की जाती है। उदाहरण के लिए, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू आईटी और प्रौद्योगिकी के लाभों से भली-भांति परिचित हैं।

काम में लापरवाही, सूरजपुर में शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई

सूरजपुर जिला शिक्षा अधिकारी ने की कार्रवाई, शिकायतों को लेकर छात्र-छात्राओं ने किया था विरोध प्रदर्शन, मामला उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिलफिली का है.

सूरजपुर। जिले में शिक्षा विभाग ने काम में लापरवाही को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। सिविल सेवा आचरण नियमों के उल्लंघन के मामले में एक बाबू और भृत्य को निलंबित कर दिया गया है। मामला उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिलफिली का है। दरअसल, कुछ दिन पहले शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिलफिली में छात्र-छात्राओं ने स्कूल में तालाबंदी कर कुछ परेशानियों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था। मामले को गंभीरता से लेते हुए नवनियुक्त जिला शिक्षा अधिकारी अशोक सिन्हा

स्कूल के बाबू और भृत्य को किया निलंबित



ने विद्यालय का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय में कार्यरत सहायक ग्रेड-3 देवी प्रसाद पर वेतन संबंधी कार्यों में लापरवाही बरतने के आरोप सामने आए। बताया गया कि उनकी लापरवाही के कारण कर्मचारियों को

विसंगति का सामना करना पड़ता रहता था। इसके अलावा नियमित रूप से विद्यालय नहीं आने और नशे की हालत में रहने संबंधी शिकायतों को भी कार्रवाई का आधार बनाया गया। इसके बाद देवी प्रसाद को निलंबित कर दिया गया है। वहीं, भृत्य पायल सिंह पर विद्यालय में हुए विरोध और तालाबंदी के दौरान छात्र-छात्राओं के साथ गलत व्यवहार की शिकायत थी। इस पर भी कार्रवाई की गई है। शिक्षा विभाग ने पायल सिंह को निलंबित करते हुए उन्हें भी चांदनी बिहारपुर क्षेत्र के एक स्कूल में अटैच किया है।

इसके अलावा विद्यालय के प्राचार्य और एक व्याख्याता के विरुद्ध भी कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को पत्र लिखा कर कार्रवाई के लिए भेजा गया है। दोनों की भूमिका को लेकर उचित कार्रवाई की अनुशंसा की गई है।

पीडीएस चावल की कालाबाजारी:132 बोरी चावल जब्त

दुर्ग भिलाई। गरीबों के राशन यानी पीडीएस चावल की कालाबाजारी के खिलाफ खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर के निर्देश पर विभाग की टीम ने अलग अलग इलाकों में दबिश देकर 132 बोरी चावल जब्त किया है। दुर्ग जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों को मिलने वाले चावल की अवैध खरीदी-बिक्री और भंडारण की शिकायतें प्रशासन को मिल रही थीं। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य विभाग की टीम ने अलग-अलग ठिकानों पर जांच शुरू



की। कार्रवाई के दौरान राजीव नगर स्थित एक ठिकाने से 60 कट्ठा चावल बरामद किया गया। इसके अलावा त्रिवेदी किराना स्टोर के गोदाम की जांच में 72 कट्ठा चावल मिला। राजीव नगर और त्रिवेदी किराना स्टोर के गोदाम से बरामद चावल की मात्रा कुल 132 बोरी यानी करीब 36 किंटल चावल है। वहीं रामनगर में कार्रवाई के दौरान सरकारी चावल से लदा ऑटो

लेकर चालक मौके से फरार हो गया। अब पुलिस और खाद्य विभाग ऑटो नंबर के आधार पर उसकी तलाश में जुटे हैं। फिलहाल खाद्य विभाग ने जब्त चावल को अपने कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। विभाग अब इस बात की जांच कर रहा है कि बरामद चावल पीडीएस का है या नहीं। इसके लिए चावल के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेजे जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि लैब रिपोर्ट और दस्तावेजों की जांच के बाद यह स्पष्ट होगा कि बरामद चावल सार्वजनिक वितरण प्रणाली का है या नहीं।

एकलव्य विद्यालय में फंदे पर लटकी मिली छात्र की लाश



जांच करने पहुंची कांग्रेस की टीम, बच्चों से की पूछताछ

बालोद। जिले के डौंडी विकासखंड में संचालित एकलव्य आवासीय विद्यालय में 10वीं के छात्र विनय कुमार की लाश फांसी के फंदे पर लटकी मिली थी, जिसके बाद पूरे परिसर में हड़कंप मच गई थी। घटना 10 सितंबर की है। मामले की जांच के लिए आज कांग्रेस की जांच समिति स्कूल पहुंची है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और जो भी दोषी हो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए।

बता दें कि 10 सितंबर को सुबह रूम नम्बर 16 में निवास करने

वाले सभी बच्चे पिटी करने चले गए, और मृतक बच्चा वहीं रूम में रुक गया। जब बच्चे पिटी से वापस आए तब देखा कि विनय का मृत शरीर रूम की खिड़की पर फांसी के फंदे पर लटका हुआ था। सूचना मिलने के बाद पुलिस और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और शव को फंदे से उतरवाकर जांच शुरू की।डौंडी पुलिस मामले की जांच कर रही है।

इस मामले में कांग्रेस की जांच

टीम एकलव्य विद्यालय पहुंची है, जिसमें जिले के तीनों विधायक डौंडीलोहारा विधायक अनिला भेंडिया, गुण्डरदेही विधायक कुंवर सिंह निसाद, संजारी बालोद विधायक संगीता सिन्हा, जिला कांग्रेस कमिटी अध्यक्ष चंद्रेश हिरवानी, कांग्रेस नेता विकास चोपड़ा, पीयूष सोनी और अन्य शामिल हैं। कांग्रेस नेताओं ने एकलव्य आवासीय विद्यालय के बच्चों से घटना के संबंध में

गणेशोत्सव में धमतरी की सड़कों में पसरा अंधेरा, स्ट्रीट लाइट बंद मवेशियों ने जमाया डेरा

धमतरी। धमतरी शहर में गणेशोत्सव का उत्साह चरम पर है। लेकिन शाम होने के बाद सड़कों पर बैठे मवेशी और अंधेरा हादसों को दावत दे रहे हैं। रायपुर-जगदलपुर मुख्य मार्ग पर अंबेडकर चौक से मकई चौक और मकई चौक से अर्जुनी चौक तक कई जगह स्ट्रीट लाइट बंद हैं।ये शहर का बेहद व्यस्त मार्ग है, जहां दिनभर और देर रात तक बड़ी संख्या में लोगों का आना-जाना रहता है।

गणेशोत्सव के कारण रात में भीड़ और यातायात सामान्य दिनों की तुलना में बढ़ गया है। ऐसे में सड़क पर पर्याप्त रोशनी नहीं होने से दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। खासकर सड़क किनारे बैठे मवेशी अंधेरे में वाहन चालकों को आसानी से नजर नहीं आते। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार अचानक सामने आए मवेशियों के कारण वाहन चालकों को ब्रेक लगाना पड़ता है।



गणेशोत्सव समितियों ने भी शहर की स्ट्रीट लाइट व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई है। समितियों का कहना है कि पंडालों में लाइटिंग से आसपास के कुछ हिस्से तक तो रोशनी पहुंचती है, लेकिन मुख्य सड़क के बड़े हिस्से में नगर निगम की स्ट्रीट लाइट बंद होने से अंधेरा बना रहता है। गणेशोत्सव के दौरान जब रात में

बड़ी संख्या में लोग घरों से निकल रहे हैं, तब मुख्य मार्गों पर रोशनी की व्यवस्था दुर्गस्त होना जरूरी है। दुकानों के बाहर लगी लाइटों से कुछ हद तक रोशनी रहती है, लेकिन दुकानें बंद होते ही सड़क पर अंधेरा और ज्यादा दिखाई देने लगता है- नागेंद्र साहू, गणेशोत्सव समिति सदस्य

स्ट्रीट लाइट बंद होने के सवाल पर महापौर रामू रोहरा ने समस्या को स्वीकार किया। उन्होंने बताया कि डिवाइडर बनने के बाद कई जगह स्ट्रीट लाइट के कनेक्शन ब्रेक हुए हैं। निगम की टीम यह पता लगाने में जुटी है कि किन-किन स्थानों पर कनेक्शन बाधित हैं और उन्हें जल्द सुधारा जाएगा।

महापौर ने 2027 को महत्वपूर्ण साल बताते हुए कहा कि जनवरी 2028 तक धमतरी का नया स्वरूप दिखाई देगा। सड़क, नाली, बिजली और पानी समेत कई

व्यवस्थाओं को बेहतर किया जाएगा। महापौर ने मुख्यमंत्री और मंत्रियों का धन्यवाद देते हुए कहा कि धमतरी विधानसभा क्षेत्र में बड़े विकास कार्यों को स्वीकृति मिली है। उनके अनुसार, उनके कार्यकाल में करीब 600 करोड़ रुपए के काम स्वीकृत हो चुके हैं और इस महीने करीब 150 करोड़ रुपये के और कार्य स्वीकृत होने की उम्मीद है। हालांकि इन सभी विकास कार्यों के बीच फिलहाल शहरवासियों का सीधा सवाल यही है कि मुख्य सड़क की बंद स्ट्रीट लाइटें आखिर कब चालू होंगी? इस पर महापौर ने कहा कि लाइटें आज-कल में आ जाएंगी और जहां-जहां कनेक्शन ब्रेक हुए हैं, उन्हें सुधारने के लिए विद्युत कर्मचारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। अब देखना होगा कि गणेशोत्सव के बीच मुख्य मार्गों पर पसरा अंधेरा कब दूर होता है और शहरवासियों को कब राहत मिलती है।

छत्तीसगढ़
प्रमुख समाचार

अजब गजब! नॉर्मल डिलीवरी से 5 किलो की बच्ची का जन्म

धमतरी। धमतरी जिला अस्पताल से एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां महिला ने 5 किलोग्राम वजनी बच्ची को नॉर्मल डिलीवरी के जरिए जन्म दिया है। राहत की बात ये है कि मां और बच्ची दोनों स्वस्थ है। बताया जा रहा है कि जिला अस्पताल के इतिहास में इतनी अधिक वजन वाली बच्ची को नॉर्मल डिलीवरी का यह दूसरा मामला है। सबसे खास बात यह है कि डिलीवरी के बाद मां और नवजात बच्ची दोनों पूरी तरह स्वस्थ हैं। जानकारी के मुताबिक, गुरु क्षेत्र के सरबदा निवासी रामेश्वर साहू की पत्नी मनीषा साहू (25) की डिलीवरी डेट निकल चुकी थी। प्रसव पीड़ा शुरू नहीं होने पर 15 सितंबर को उन्हें धमतरी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों के मुताबिक, 1 सितंबर को हुई सोनोग्राफी में बच्ची का वजन करीब 3.5 किलो बताया गया था। इसके करीब 15 दिन बाद बच्ची का वजन बढ़कर 5 किलो हो गया। इसके बाद 16 सितंबर को दोपहर ठीक 1 बजकर 1 मिनट पर मनीषा साहू की नॉर्मल डिलीवरी हुई और उन्होंने 5 किलो वजनी बच्ची को जन्म दिया।

राजगामी संपदा न्यास करेगी डीएम से उच्चस्तरीय जांच की मांग

राजनांदगांव। शहर के प्रतिष्ठित वाइडनेयर स्कूल को राजगामी संपदा न्यास द्वारा दी गई शासकीय लीज भूमि के अवैध क्रय-विक्रय के मामले में अब कार्रवाई होना तय माना जा रहा है। राजगामी संपदा न्यास समिति ने इस बहुचर्चित प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर को पत्र लिखकर जांच के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने की मांग करेगी। शिकायतकर्ता क्रिष्णेश पॉल ने बताया कि वर्ष 1975 में तत्कालीन कलेक्टर एवं राजगामी संपदा न्यास द्वारा लालबाग स्थित दो अलग-अलग स्थानों पर लगभग 5 एकड़ भूमि वाइडनेयर स्कूल के संचालन के लिए (शैक्षणिक उद्देश्य से) आवंटित की गई थी। नियमानुसार राजगामी संपदा की लीज पर दी गई भूमि को बिना शासन एवं न्यास की पूर्व अनुमति के किसी अन्य संस्था या व्यक्ति हस्तांतरित या विक्रय नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद, स्कूल को संचालन करने वाली संस्था ने न्यास व कलेक्टर को बिना कोई सूचना दिए इस बेशकीमती शासकीय भूमि को दो अलग- अलग संस्थाओं को विक्रय कर दिया।

सबसे पुराना पार्क शहीद पार्क की बदलेगी तस्वीर

जगदलपुर। लंबे अरसे से अपने कायाकल्प का इंतजार कर रहे शहर के सबसे पुराने पार्कों में से एक शहीद पार्क की दशा बदलने वाली है। महापौर संजय पांडे ने नगर निगम के अधिकारियों के साथ पार्क का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए अधिकारियों को सुविधाओं में सुधार के साथ-साथ विस्तार के निर्देश दिए हैं। शहर के हृदय स्थल में स्थित शहीद पार्क में एक समय लोगों की चहल-पहल से गुलजार रहा करता था, लेकिन समय के साथ पार्क की तस्वीर बदल गई। बच्चों के लिए चलाई जाने वाली रेल गाड़ी की जगह टॉय ट्रेन ने ले ली, लेकिन वह भी बंदहाल हो गया। पार्क के आस-पास बेतरतीब निर्माण होने के कारण ड्रेनेज सिस्टम ने भी दम तोड़ दिया है, अब हल्की बारिश में ही पार्क के अंदर पानी भर जाता है। बच्चों के लिए लगाए गए झूलों की मरम्मत नहीं होने से बंदहाल है। नगर निगम ने पूर्व में यहां ओपन जिम शुरू किया था, लेकिन वह भी उपेक्षित नजर आने लगा। पार्क में हर दिन हजारों की संख्या में लोग वॉक करने पहुंचते हैं।

दो अधूरे अंडरब्रिज का 3 साल से दंश झेल रही संस्कारधानी

राजनांदगांव। सालभर के अंदर पूरा होने वाला गौरीनगर और रेलवे स्टेशन अंडरब्रिज का काम तीन साल बीतने के बाद भी अधूरा है। रेलवे द्वारा बरती जा रही है यह लापरवाही अब लोगों के मौत का कारण बन रही है। इसे लेकर कई बार आंदोलन किए गए हैं, लेकिन रेलवे अपनी जिम्मेदारी और जवाबदारी को निभाने में नाकाम साबित हुआ है। गौरीनगर और स्टेशनपारा अंडरब्रिज निर्माण के चलते पटरीपार के करीब पचास हजार से अधिक लोगों आवाजाही के लिए परेशान होना पड़ रहा हैं। दोनों अंडरब्रिज निर्माण का डेडलाइन वर्ष 2024 तय किया गया था। लेकिन वर्तमान में बार-बार किसी न किसी वजह से काम के बंद होने और ठेकेदार के कार्य को गंभीरता से नहीं लिए जाने के कारण अब तक निर्माण पूरा नहीं हुआ है। बता दे अंडरब्रिज का कार्य पिछले लंबे समय से अधूरा होने के चलते वाहन चालकों को ओव्हरब्रिज से ही जाने एकमात्र विकल्प है, जिसके चलते यहां रोजाना वाहनों का जाम लगा रहता हैं।

पहले कीचड़ में थम जाते थे कदम, अब पक्की सड़क पर दौड़ती है जिंदगी

कोरबा। जिले के दूरस्थ ग्राम पंचायत मदनपुर के आश्रित ग्राम मांझीपारा में रहने वाले विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों के लिए गांव तक पहुंचने वाली राह लंबे समय से परेशानी का कारण बनी हुई थी। मदनपुर से मांझीपारा तक का करीब 2.2 किलोमीटर का रास्ता कच्चा था। गर्मी में धूल और बारिश में कीचड़ इस रास्ते की पहचान बन जाता था। गांव के लोगों के लिए यह केवल एक रास्ता नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली कई मुश्किलों की वजह था। बारिश शुरू होते ही इस कच्चे रास्ते पर चलना मुश्किल हो जाता था। किसी को अस्पताल जाना हो, बच्चों को स्कूल पहुंचाना हो या जरूरी काम से शहर जाना हो, हर बार इसी रास्ते से गुजरना पड़ता था। विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों की बसाट वाले ऐसे दूरस्थ क्षेत्रों को मुख्य मार्गों से जोड़ने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) के तहत सड़क निर्माण को प्राथमिकता दी गई।

पंडित चक्रपाणी स्कूल में शिक्षक पर शराब के नशे में पहुंचने का आरोप

बलौदा बाजार। जिला मुख्यालय स्थित पंडित चक्रपाणी मल्टीपरपज स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम विद्यालय एक बार फिर विवादों में है। इस बार स्कूल के एक शिक्षक पर कथित तौर पर शराब के नशे में स्कूल पहुंचने, छात्राओं से गाली-गलौज करने और विरोध करने पर मारपीट करने का आरोप लगा है। घटना की जानकारी सामने आने के बाद विद्यार्थियों में नाराजगी की स्थिति बताई जा रही है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर के निर्देश पर प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी और तहसीलदार स्कूल पहुंचे। अधिकारियों द्वारा पूरे मामले की जानकारी ली जा रही है। वहीं इस मामले की कवरेज करने पहुंचे मीडियाकर्मियों के साथ स्कूल की प्राचार्य वंदनी श्रीवास्तव के कथित व्यवहार को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया है।



मीडियाकर्मियों का आरोप है कि प्राचार्य ने उन्हें अपने कक्ष से बाहर निकाल दिया और कहा कि स्कूल परिसर में मीडिया का प्रवेश प्रतिबंधित है। एनएसयूआई ने भी मामले को लेकर प्रदर्शन किया है। जानकारी के अनुसार, गुरुवार को स्कूल के शिक्षक नरेश तिवारी के कथित तौर पर शराब के नशे में स्कूल पहुंचने की बात सामने आई। आरोप है कि इस दौरान उन्होंने छात्राओं के साथ

गाली-गलौच की। आरोप है कि शिक्षक के व्यवहार से छात्राएं असहज हुईं और उन्होंने इसका विरोध किया। इसके बाद विवाद बढ़ने और छात्राओं के साथ मारपीट किए जाने की शिकायत सामने आई है। हालांकि शिक्षक द्वारा छात्राओं के साथ मारपीट किए जाने और उनके शराब के नशे में होने के आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। प्रशासनिक जांच के बाद ही पूरे

घटनाक्रम की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। स्कूल से जुड़े लोगों के अनुसार, आरोपी शिक्षक पर पहले भी शराब पीकर स्कूल आने के आरोप लगते रहे हैं। गुरुवार की घटना के बाद विद्यार्थियों और उनके परिजनों के बीच इसको लेकर नाराजगी बताई जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि शिक्षक वास्तव में नशे की हालत में स्कूल पहुंचे थे तो स्कूल प्रबंधन की ओर से उस समय क्या कार्रवाई की गई और विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए। घटना के बाद छात्राएं और अन्य विद्यार्थी शिकायत लेकर स्कूल की प्राचार्य के पास पहुंचे। विद्यार्थियों का आरोप है कि उन्होंने शिक्षक के व्यवहार और कथित मारपीट की जानकारी प्राचार्य को दी। हालांकि विद्यार्थियों की शिकायत पर तत्काल क्या कार्रवाई की गई, इसे लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है।

बिना नहाए कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीण, कलेक्टर से लगाई ये गुहार

मुंगेली। जिले के ग्राम पंचायत डोड़ा के ग्राम डोड़ा से पिछले करीब 45 दिनों से विद्युत के ट्रांसफार्मर खराब होने के कारण बिजली व्यवस्था प्रभावित है। ग्रामीणों का कहना है कि कुछ दिन पहले विद्युत विभाग द्वारा 100 किलोवाट का नया ट्रांसफार्मर लगाया गया था, लेकिन शॉर्ट सर्किट होने के कारण यह ट्रांसफार्मर महज एक दिन बाद ही जल गया। इसके बाद गांव में एक बार फिर बिजली संकट गहरा गया है। ग्रामीणों के मुताबिक, बिजली बंद होने से पेयजल, कृषि कार्य और रोजमर्रा

के जरूरी काम प्रभावित हो रहे हैं। पेयजल व्यवस्था प्रभावित होने के कारण ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए करीब 2 से 3 किलोमीटर दूर दूसरे गांव तक जाना पड़ रहा है। वहीं बिजली नहीं होने से किसानों को कृषि कार्यों में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिजली और पेयजल संकट की स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि समस्या की शिकायत लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे ग्रामीणों में से कुछ ग्रामीणों ने बताया कि पानी की समस्या के चलते वे नहाए तक नहीं थे। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में बिजली बंद होने से पानी की व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित है, जिसके कारण

रोजमर्रा के कामों के साथ व्यक्तिगत जरूरतों के लिए भी पानी जुटाना मुश्किल हो रहा है। इसी समस्या को लेकर ग्रामीण अपनी परेशानी लेकर कलेक्टर के पास पहुंचे और जल्द समाधान की मांग की। बिजली काम हो जाने की गांव में जल जीवन मिशन योजना के तहत घर-घर पानी पहुंचाने की व्यवस्था की गई है, लेकिन मौजूदा समय में लोगों के घरों तक योजना का पानी नहीं पहुंच रहा है। बिजली संकट के कारण पानी की सप्लाई प्रभावित होने की बात ग्रामीणों द्वारा कही जा रही है। ऐसे में एक ओर जहां ग्रामीणों को पेयजल के लिए 2 से 3 किलोमीटर दूर दूसरे गांव तक जाना पड़ रहा है।



जैव विविधता संरक्षण में कीर्तिमान स्थापित करता छत्तीसगढ़

जंगल, जल, जमीन और जनभागीदारी के संगम से
गढ़ी जा रही हरित भविष्य की नई इबारत



“ प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चलना ही मनुष्य और धरती के भविष्य की रक्षा का मार्ग है। जैव विविधता का संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा और सतत विकास की हमारी प्रतिवद्धता है।

– नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

धरती पर जीवन का अस्तित्व केवल मानव पर नहीं, बल्कि उन लाखों जीव-जंतुओं, वनस्पतियों, जल स्रोतों और प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्रों पर भी निर्भर करता है जो जैव विविधता का आधार हैं। जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण और जैविक प्रजातियों के घटते अस्तित्व की चुनौती के बीच छत्तीसगढ़ जैव विविधता संरक्षण का एक सफल मॉडल बनकर उभर रहा है। राज्य का लगभग 44 प्रतिशत भूभाग वनाच्छादित है। आदिवासी समाज की प्रकृति आधारित जीवनशैली और सरकार की दूरदर्शी नीतियों मिलकर संरक्षण और विकास के बीच संतुलन की नई कहानी लिख रही हैं।

“ छत्तीसगढ़ की पहचान केवल खनिज संपदा से नहीं, बल्कि उसकी जैविक समृद्धि और प्राकृतिक विरासत से भी है। हमारी सरकार विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित करते हुए जैव विविधता संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।

– विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

हरित धरोहर का प्रहरी बना छत्तीसगढ़

बस्तर के साल वन, अचानकमार के जैविक गलियारे, उदंती सीतनदी के वन्यजीव आवास, इंद्रावती की प्राकृतिक संपदा और मैकल पर्वतमाला का हरित विस्तार राज्य को विशिष्ट पहचान देते हैं। प्रदेश के जंगल हजारों वनस्पति प्रजातियों, दुर्लभ औषधीय पौधों, पक्षियों, वन्यजीवों और सूक्ष्म जीवों का प्राकृतिक घर हैं। यही कारण है कि जैव विविधता संरक्षण को राज्य सरकार की विकास रणनीति का अभिन्न हिस्सा बनाया गया है।



रामसर साइट का गौरव कोपरा बना अंतरराष्ट्रीय पहचान का केंद्र



बिलासपुर स्थित कोपरा जलाशय को राज्य की पहली रामसर आर्द्रभूमि (Ramsar Wetland) का दर्जा मिला। यह उपलब्धि जलीय जैव विविधता, आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रवासी पक्षियों के संरक्षण की दिशा में ऐतिहासिक कदम है।

गांव-गांव पहुंच रहा जैव विविधता संरक्षण अभियान

जैव विविधता प्रबंधन समितियों (BMCs) राज्य के गांवों में सक्रिय है। स्थानीय समुदायों को संरक्षण कार्यों से जोड़कर ग्राम स्तर पर वनस्पतियों, जीव-जंतुओं, पारंपरिक ज्ञान और प्राकृतिक संसाधनों का दस्तावेजीकरण किया जा रहा है।



पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर (PBR) गांवों की प्रकृति का जीवंत दस्तावेज

गरियाबंद जिले के टौरंगा ग्राम पंचायत में राज्य का पहला पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर तैयार किया गया। इसमें सैकड़ों जैविक संसाधनों का वैज्ञानिक दस्तावेजीकरण किया गया है।

24	34	174	36	27	44	13
कृषि फसलें	औषधीय पौधे	जंगली वनस्पतियां	पक्षी प्रजातियां	वन्यजीव	तितली प्रजातियां	मछली एवं जलीय जीव प्रजातियां

यह पहल स्थानीय जैव विविधता संरक्षण का राष्ट्रीय स्तर पर अनुकरणीय मॉडल बनी।

जैविक खेती से पर्यावरण संरक्षण का नया अध्याय

रासायनिक खेती से मिट्टी, जल और जैव विविधता को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए राज्य सरकार ने पांच जिलों को पूर्ण जैविक जिले के रूप में विकसित किया है।

- गरियाबंद
- बीजापुर
- सुकमा
- दत्तेवाड़ा
- नारायणपुर



इससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ी है, प्राकृतिक परागण तंत्र मजबूत हुआ है। तथा कृषि जैव विविधता को संरक्षण मिला है।

लौट रही हैं दुर्लभ प्रजातियां, मजबूत हो रहा पारिस्थितिक संतुलन

बारनवापारा अभयारण्य और अचानकमार जैसे संरक्षित क्षेत्रों में दुर्लभ प्रजातियों की पुनः उपस्थिति दर्ज की गई है।



विशाल भारतीय गिलहरी
(रतूफा इंडिका)

काले हिरण

बाघ संरक्षण कार्यक्रमों से राज्य में बाघों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है।

वन्यजीव संरक्षण

जैव विविधता की सुरक्षा कवच

राज्य में अनेक विशेष कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं-

- जंगली भैंसा संरक्षण कार्यक्रम
- पहाड़ी मैना संरक्षण पहल
- हाथी मानव संघर्ष प्रबंधन
- वन्यजीव गलियारा संरक्षण
- प्राकृतिक आवास पुनर्स्थापन



जनजातीय समाज सबसे बड़ा संरक्षण साथी

छत्तीसगढ़ का आदिवासी समाज सदियों से प्रकृति के साथ सह-अस्तित्व की परंपरा निभाता आया है।



घर-आंगन में विविध पौधों का संरक्षण, पारंपरिक औषधीय ज्ञान और सामुदायिक संसाधन प्रबंधन आज भी संरक्षण का सबसे प्रभावी उदहरण हैं।

जलवायु परिवर्तन से लड़ाई में छत्तीसगढ़ की हरित शक्ति

स्वस्थ वन और समृद्ध जैव विविधता कार्बन अवशोषण बढ़ाकर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

- कार्बन सिंक का कार्य कर रहे हैं।
- भुजल संरक्षण में योगदान दे रहे हैं।
- तापमान संतुलन बनाए रख रहे हैं।
- कृषि और आजीविका को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं।



जैव विविधता संरक्षण में प्रमुख उपलब्धियां

- राज्य का पहला रामसर स्थल – कोपरा जलाशय
- पहला पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर – टौरंगा (गरियाबंद)
- जैव विविधता प्रबंधन समितियों का व्यापक विस्तार
- पांच पूर्ण जैविक जिलों का विकास
- दुर्लभ प्रजातियों की पुनः उपस्थिति



- बाघ संरक्षण में उल्लेखनीय सफलता
- जंगली भैंसा एवं पहाड़ी मैना संरक्षण कार्यक्रम
- सामुदायिक वन प्रबंधन को बढ़ावा
- जनजातीय पारंपरिक ज्ञान का दस्तावेजीकरण
- आर्द्रभूमि एवं प्राकृतिक आवास संरक्षण अभियान

प्रकृति बचेगी तो भविष्य सुरक्षित रहेगा

जैव विविधता केवल पर्यावरण का विषय नहीं है, बल्कि जीवन, आजीविका, जल, खाद्य सुरक्षा और मानव सभ्यता के अस्तित्व का आधार है। छत्तीसगढ़ ने संरक्षण और विकास के बीच संतुलन स्थापित करते हुए यह सिद्ध किया है कि प्राकृतिक संसाधनों को बचाकर भी समृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है।

जंगल बचेंगे, जैव विविधता बचेगी, तभी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित रहेगा।



छत्तीसगढ़ सरकार की प्रतिबद्धता – समृद्ध प्रकृति, समृद्ध प्रदेश, सुरक्षित भविष्य



जशपुर के 2600 विद्यालयों में गूंजा ‘स्वच्छ भारत, विकसित भारत’ का संदेश

रायपुर। ‘स्वच्छ भारत, विकसित भारत’ की परिकल्पना को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से जशपुर जिले के लगभग 2600 विद्यालयों में चित्रकला एवं भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। इन गतिविधियों में विद्यार्थी उत्साहपूर्वक सहभागिता कर स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, स्वस्थ जीवनशैली, सामाजिक जागरूकता और राष्ट्र निर्माण से जुड़े विषयों पर अपनी रचनात्मक प्रतिभा एवं विचारों को अभिव्यक्त कर रहे हैं। प्रतियोगिताएं 19 सितंबर 2026 तक जारी रहेंगी।

चित्रकला प्रतियोगिता में विद्यार्थियों द्वारा स्वच्छ विद्यालय, स्वच्छ गांव-शहर, कचरा प्रबंधन, प्लास्टिक मुक्त वातावरण, हरित पर्यावरण और जल संरक्षण जैसे विषयों को

चित्रकला और भाषण प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों ने स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और विकसित भारत की परिकल्पना को किया अभिव्यक्त

चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है। रंगों और कल्पनाशीलता के माध्यम से विद्यार्थी स्वच्छ एवं सुंदर भारत की अपनी परिकल्पना को प्रभावी ढंग से सामने रख रहे हैं। वहीं भाषण प्रतियोगिता में विद्यार्थी स्वच्छता के महत्व तथा विकसित भारत के निर्माण में नागरिकों की भूमिका पर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक स्वच्छता, कचरे का उचित निपटान, स्वच्छ पेयजल, पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता को दैनिक जीवन की आदत बनाने जैसे विषयों पर विद्यार्थी अपने विचार साझा कर रहे हैं। इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से विद्यार्थियों में केवल रचनात्मक अभिव्यक्ति ही नहीं, बल्कि



सामाजिक उत्तरदायित्व और राष्ट्र निर्माण की भावना को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। विद्यार्थियों को यह संदेश दिया जा रहा है कि स्वच्छता किसी एक अभियान तक सीमित नहीं, बल्कि दैनिक जीवन की आदत और सामूहिक जिम्मेदारी है। विद्यालयों में आयोजित इन गतिविधियों से विद्यार्थियों में स्वच्छता संस्कार, पर्यावरणीय चेतना और जिम्मेदार नागरिक बनने की भावना विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है। विद्यार्थियों की सहभागिता के माध्यम से स्वच्छता और जागरूकता का संदेश परिवार एवं समुदाय तक पहुंचाने की दिशा में भी सकारात्मक वातावरण बन रहा है।

जिले के विभिन्न विद्यालयों में प्रतियोगिताओं को लेकर विद्यार्थियों और शिक्षकों में उत्साह का माहौल है। शिक्षक विद्यार्थियों को विषय की समझ विकसित करने, रचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करने तथा स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने में सहयोग कर रहे हैं। ‘स्वच्छ भारत, विकसित भारत’ थीम पर आधारित ये गतिविधियां विद्यालय स्तर से स्वच्छता और जिम्मेदार नागरिकता की भावना को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल हैं। विद्यार्थियों की रचनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से स्वच्छ, स्वस्थ, जागरूक एवं विकसित भारत के निर्माण में सहभागिता का संदेश समाज तक पहुंच रहा है।

नए दौर की अर्थव्यवस्था के लिए तैयार हो रहा छत्तीसगढ़, भविष्य के उद्योगों पर हमारा फोकस: मुख्यमंत्री

भविष्य के उद्योगों का नया केन्द्र बनने की ओर अग्रसर छत्तीसगढ़ : साय

मुख्यमंत्री साय ने रायपुर में किया ‘इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर –2026’ का शुभारंभ

देशभर के 300 से अधिक एमएसएमई उद्यमी तीन दिवसीय औद्योगिक मेले में ले रहे हिस्सा

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर के साईंस कॉलेज मैदान में लघु उद्योग भारती द्वारा आयोजित तीन दिवसीय ‘इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर-2026’ का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने देश के विभिन्न राज्यों से आए उद्यमियों, निवेशकों और औद्योगिक प्रतिनिधियों का छत्तीसगढ़ की धरती पर स्वागत करते हुए उन्हें प्रदेश की विकास यात्रा में सहभागी बनने और यहां उपलब्ध निवेश की व्यापक संभावनाओं का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया। श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ आज अपनी पारंपरिक औद्योगिक ताकत के साथ नई अर्थव्यवस्था और उभरते उद्योगों की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। खनिज, ऊर्जा, वन संपदा, पर्याप्त मानव संसाधन और देश के मध्य में अनुकूल भौगोलिक स्थिति हमारी स्वाभाविक ताकत है।

नई औद्योगिक विकास नीति से छत्तीसगढ़ में निवेश को मिली नई गति, प्रस्तावों के साथ धरातल पर भी उतर रही परियोजनाएं: मुख्यमंत्री श्री साय



‘बस्तर में पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए व्यापक संभावनाएं’ मुख्यमंत्री श्री साय ने बस्तर की प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध जनजातीय संस्कृति और पर्यटन संभावनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में उद्योगों के साथ पर्यटन क्षेत्र में भी निवेश की व्यापक संभावनाएं हैं। राज्य सरकार पर्यटन को रोजगार और स्थानीय आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि बस्तर के जलप्रपात, घने वन, प्राकृतिक स्थल और विशिष्ट जनजातीय संस्कृति देश-दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। होम-स्टे जैसी पहलों के माध्यम से पर्यटन को सीधे स्थानीय परिवारों की आजीविका से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

‘स्थानीय युवाओं के रोजगार से जुड़ेगा औद्योगिक विकास’ मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि औद्योगिक विकास का वास्तविक लाभ तभी है, जब उससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ें। इसीलिए नई औद्योगिक नीति में स्थानीय रोजगार को विशेष महत्व दिया गया है। अधिक संख्या में स्थानीय युवाओं को रोजगार देने वाले उद्योगों के लिए विशेष प्रोत्साहन के प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य ऐसा औद्योगिक विकास है, जिसमें प्रदेश का युवा केवल रोजगार तलाशने वाला न रहे, बल्कि अपने कौशल, नवाचार और उद्यमशीलता के बल पर रोजगार देने वाला भी बने। एमएसएमई और स्टार्टअप इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। सरकार युवाओं को कौशल, तकनीक, बाजार और उद्यमिता के अवसरों से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

सेवा संकल्प अभियान में बच्चों की रचनात्मक अभिव्यक्ति की गूंज



नुकड़ नाटक, रंगोली, ड्रॉइंग एवं भाषण प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों ने दिखाई राष्ट्र निर्माण की कल्पना, युवा शक्ति, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और आत्मनिर्भरता को बनाया केन्द्र

रायपुर। ‘सेवा संकल्प अभियान’ के अंतर्गत गौरेला पेन्ड्रा मरवाही जिले में विद्यार्थियों की रचनात्मक प्रतिभा, जनजागरूकता और राष्ट्र निर्माण की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। अभियान के तहत विद्यार्थियों ने कला, अभिनय और अभिव्यक्ति के माध्यम से विकसित भारत की अपनी

कल्पना को प्रस्तुत किया। जिले के गौरेला स्थित रानी दुर्गावती चौराहा के पास आईटीआई गौरेला एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की बालिकाओं द्वारा नुकड़ नाटक और रंगोली के माध्यम से जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं ‘पच्चीस करोड़ बच्चों के सपनों का भारत’ थीम के तहत जिले के शासकीय एवं निजी सहित सभी 905 विद्यालयों में ड्रॉइंग एवं भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

रानी दुर्गावती चौराहा में आयोजित नुकड़ नाटक में बालिकाओं ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में सेवा भाव, नमो गाथा तथा देश को समृद्ध, सशक्त और मजबूत राष्ट्र बनाने में युवा

शक्ति की भूमिका को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। नाटक के माध्यम से विद्यार्थियों ने यह संदेश दिया कि देश के विकास में युवाओं की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण है और शिक्षा, कौशल, मेहनत तथा नवाचार के माध्यम से युवा राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। नुकड़ नाटक में युवाओं को आत्मनिर्भर बनने, स्वरोजगार के अवसरों का लाभ उठाने तथा अपनी क्षमता और कौशल के अनुरूप आर्थिक गतिविधियों से जुड़ने के लिए प्रेरित किया गया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एवं मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से युवाओं को स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ने का संदेश भी दिया गया।

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

कांग्रेस नेताओं के दिमाग में दीप नहीं जलता : संजय श्रीवास्तव रायपुर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री के रूप में जनसेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने एवं 76वें जन्मदिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा देशभर में आशीर्वाद के दीप जलाने के आह्वाण को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष श्री संजय श्रीवास्तव ने तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि दीप जलाना भारतीय संस्कृति, सनातन परंपरा और जनआशीर्वाद का प्रतीक है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को इस पवित्र भाव का भी उपहास उड़ाने में संकोच नहीं होता। श्री संजय श्रीवास्तव ने कहा कि भूपेश बघेल की मति खराब हो चुकी है, उन्हें दीप के महत्व और उसके पीछे छिपे सनातनी भाव को समझना चाहिए। दीप केवल मिट्टी और तेल से बना एक साधन नहीं, बल्कि हमारी आस्था, संस्कार और शुभकामनाओं का प्रतीक है। जिस प्रकार दीपावली में दीप प्रज्वलित कर मां लक्ष्मी का स्वागत किया जाता है और घर में सुख-समृद्धि की कामना की जाती है। आँओं, उसी प्रकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस पर आशीर्वाद के दीप जलाकर देश की जनता ने उनके दीर्घायु, उसम स्वास्थ्य एवं निरंतर राष्ट्रसेवा की कामना की है।

झीरम केस में एनआईए की जांच पर सवाल उठाने पर विजय शर्मा का कांग्रेस पर तंज जगदलपुर। झीरम घाटी नरसंहार मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने 39 लोगों को आरोपी बनाया था। इनमें से 14 लोग सरेंडर करके सामान्य जिंदगी जी रहे हैं। ये जानकारी डिप्टी सीएम और गृहमंत्री विजय शर्मा ने दी। बुधवार को एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने इस केस में 10 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई थी, उसके अगले दिन विजय शर्मा मां दत्तेश्वरी एयरपोर्ट पर मीडिया से बात कर रहे थे। विजय शर्मा ने बताया कि उनकी जानकारी के हिसाब से एनआईए ने 39 लोगों को आरोपी बनाया था। ये सभी माओवादी संगठन के अलग-अलग पदों पर थे। इनमें से 9 न्यूट्रलाइज हो चुके हैं, 11 पर कोर्ट का फैसला आ चुका है। इनमें से एक की मौत हो चुकी है। 14 लोग सरेंडर करके पुनर्वासित हैं। उन्होंने कहा कि एनआईए की जांच बहुत सटीक है, जिस पर बेवजह राजनीति करने की कोशिश की गई। एनआईए की सही जांच के आधार पर ही एनआईए कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के न्यायिक इतिहास का सबसे बड़ा फैसला सुनाया है। एनआईए की जांच पर सवाल उठाने वाले कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर तंज कसते हुए विजय शर्मा ने कहा, मुझे बताओ किसकी जेब में झीरम के सबूत थे।

एक साथ गूंजी तीन किलकारियां, सामान्य प्रसव से जन्मे तीन बेटे दत्तेवाड़ा। जिला अस्पताल के प्रसव कक्ष में बुधवार को एक साथ तीन किलकारियां गूँजीं। कटेकल्याण क्षेत्र की हाई रिस्क गर्भवती ने सामान्य प्रसव से तीन बेटों को जन्म दिया। दोपहर करीब 3 से 3.30 बजे के बीच हुए प्रसव में तीनों नवजातों का वजन 1870, 1875 और 1750 ग्राम रहा। जन्म के बाद तीनों की स्थिति स्थिर बताई गई है। कम वजन को देखते हुए उन्हें विशेष निगरानी के लिए एसएनसीयू में भर्ती किया गया है। इस मामले में गर्भावस्था के दौरान ही महिला की स्थिति को हाई रिस्क के रूप में चिन्हित कर लिया गया था। कटेकल्याण की स्वास्थ्य टीम महिला के नियमित संपर्क में रही। समय-समय पर सोनोग्राफी कराई गई और मितानिन के माध्यम से फॉलोअप किया गया। साथ ही आयरन और कैल्शियम की गोलियों के नियमित सेवन के लिए भी महिला को प्रेरित किया गया।

एसईसीएल मुख्यालय में स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 का शुभारंभ बिलासपुर। शुक्रवार 18 सितंबर को एसईसीएल मुख्यालय में स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 का शुभारंभ स्वच्छता शपथ के साथ हुआ। कार्यक्रम का आयोजन मुख्य प्रशासनिक भवन स्थित आंगतुक कक्ष में किया गया। इस अवसर पर निदेशक (मानव संसाधन) श्री बिरंची दास, निदेशक (वित्त) श्री डी. सुनील कुमार, निदेशक (तकनीकी) संचालन श्री रमेश चंद्र महापात्र तथा निदेशक (तकनीकी) योजना/परियोजना (अति. प्र.) श्री नृपेंद्र नाथ सहित विभिन्न विभागध्यक्ष, अधिकारी-कर्मचारी एवं श्रम संघ प्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सभी लोगों ने स्वच्छता के प्रति सजग रहने, हर वर्ष 100 घंटे यानी प्रत्येक सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करने, अपने आसपास एवं कार्यस्थल को साफ-सुथरा रखने तथा स्वच्छता को जीवनशैली का हिस्सा बनाने की शपथ ली। भारत सरकार के निदेशानुसार एसईसीएल द्वारा स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों एवं जन-जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा।

विकसित भारत 2047 के संकल्प की सिद्धि में प्रत्येक नागरिक की भूमिका महत्वपूर्ण : अमर अग्रवाल

आशीर्वाद के एक लाख दीपों से जगमगाया शिवरीनारायण

रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन एवं राष्ट्रसेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित ‘सेवा संकल्प अभियान’ के तहत जांजगीर-चांपा जिले में सेवा, जनभागीदारी और राष्ट्र निर्माण की भावना का भव्य प्रदर्शन हुआ। शिवरीनारायण स्थित पावन महानदी तट पर आयोजित ‘आशीर्वाद का दीप’ कार्यक्रम में एक लाख दीप प्रज्वलित किए गए। एक साथ जगमगाए दीपों से महानदी घाट का दृश्य आलोकित हो उठा और सेवा, समर्पण तथा विकसित भारत के संकल्प का संदेश जन-जन तक पहुंचा। कार्यक्रम में बिलासपुर

विधायक अमर अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर पवन साय, पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, पूर्व संसदीय सचिव अम्बेश जांगड़े, राजेश्वरी श्री महंत राम सुंदर दास, नगर पंचायत शिवरीनारायण अध्यक्ष श्री राहुल थवाईट, कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी, गणमान्य नागरिक एवं बड़ी संख्या में जिलेवासी उपस्थित रहे। इस अवसर पर महानदी घाट पर महाआरती का भी आयोजन किया गया। विधि-विधान एवं श्रद्धा के साथ संपन्न महाआरती से पूरा घाट भक्तिमय वातावरण से भर उठा।



विधायक अमर अग्रवाल ने भगवान विश्वकर्मा जयंती की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रसेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के

अवसर पर ‘आशीर्वाद का दीप’ के माध्यम से जनभागीदारी का यह आयोजन सेवा और राष्ट्र निर्माण की भावना को मजबूत कर रहा है। उन्होंने कहा कि

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने वैश्विक स्तर पर अपनी मजबूत पहचान स्थापित की है। भारतीय संस्कृति और विरासत को आगे बढ़ाने तथा राष्ट्र के विकास के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। श्री अग्रवाल ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में प्रत्येक नागरिक की भूमिका महत्वपूर्ण है। ‘आशीर्वाद का दीप’ में प्रज्वलित प्रत्येक दीप विकसित भारत 2047 के संकल्प के प्रति जनभागीदारी और प्रतिबद्धता का प्रतीक है। ये दीप सेवा, संकल्प और राष्ट्र निर्माण की भावना को जन-जन तक पहुंचाने का माध्यम बने हैं।

बीजापुर। जिले में स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद जिला मुख्यालय के अलावा भोपालपटनम, भैरमगढ़ और आवापल्ली क्षेत्र से भी बढ़े हुए बिजली बिल की शिकायतें सामने आ रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जिन घरों में पहले 200 से 300 रुपये तक बिजली बिल आता था, वहां अब 4 से 5 हजार रुपये तक बिल पहुंच रहा है। वहीं 500 से 1000 रुपये तक आने वाला मासिक बिल भी कई उपभोक्ताओं के लिए हजारों रुपये तक पहुंच गया है। आवापल्ली क्षेत्र में महिला उपभोक्ता चमप्पा गुलधर के घर लुधर के अनुसार उनके घर में सामान्य घरेलू उपयोग के अलावा बिजली की खपत करने वाला कोई बड़ा उपकरण या साधन नहीं है। इसके बावजूद इतनी अधिक राशि का बिल आने से परिवार परेशान है। महिला ने बताया कि बिल की

राशि में से लगभग 30 हजार रुपये जमा करने के बाद भी उनका बिजली कनेक्शन काट दिया गया। मामले को लेकर महिला ने बीजापुर विधायक विक्रम शाह मंडवी से मुलाकात कर आम जन समस्या बताई। विधायक ने बिजली विभाग के अधिकारी से फोन पर चर्चा कर मामले की जांच कराने तथा मीटर की रीडिंग की जांच कर वास्तविक खपत के आधार पर सही बिजली बिल जारी करने के निर्देश दिए। ग्रामीणों का कहना है कि यह समस्या केवल एक उपभोक्ता तक सीमित नहीं है। कई घरों और दुकानों में स्मार्ट मीटर लगने के बाद अपेक्षाकृत अधिक बिल आने की शिकायतें सामने आ रही हैं।